SHRI OM MEHTA : We have been taking both the things together up to this time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The Business Advisory Committee had allotted time together for both the measures. If we are having separa'e discussions, then we have to apportion time for the two measures. That is why I said that for the Budget there will be approximately one hour and for the Appropriation Bill approximately one hour.

SOME HON. MEMBERS : No, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : All right. Now, Mr. Misra, please. ... On the Budget, please.

THE BUDGET (PUNJAB), 1971-72
General Discussion

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : यह अनपार्लियामेंटरी है, देखिये, रीजनेबिल डिसकशन रोक देंगे आप !

श्री एस० डी० मिश्र (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, आज इस सदन में जो पंजाब का बजट पेश हुआ है, उस सम्बन्ध में चर्चा करते हुये कोई बड़ी खुशी हम लोगों को नहीं होती, क्योंकि अगर राज्य सरकारों का बजट धीरे-धीरे बराबर केन्द्र में . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Bhupesh Gupta wants to detain the House by delaying consideration of the Preventive Dentention Bill.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) : Sir. on a personal explanation and on a point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : There is no point of order.

SHRI BHUPESH GUPTA : Sir, the remarks you made should be expunged. If you do not expunge them, then permit me to move a resolution.

SHRI M. N. KAUL (Nominated) : Resolution on what ?

SHRI BHUPESH GUPTA : He said that I want to delay the Preventive Detention Bill. First of all, there is no Bill as Preventive Detention Bill. There is an Act called . . .

SHRI PITAMBER DAS (Uttar Pradesh) : Only when there was no time left for separate discussions.

SHRI BHUPESH GUPTA : Sir, I rise on a point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Please sit down.

SHRI BHUPESH GUPTA : No, Sir. . . .

(*Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Please sit down.

SHRI NIREN GHOSH (West Bengal) : We do not agree. It cannot be imposed upon us.

(Interruptions)

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Please sit down.

SHRI MAHAVIR TYAGI (Uttar Pradesh) : The Security Bill may also be discussed.

Mr. DEPUTY CHAIRMAN : We have been following the practice. If the Members want a separate discussion both for the Budget and the Appropriation Bill. I cannot have any objection. But this is the procedure. In that case we have to take into account the time earmarked for the two matters. Therefore, I think we can have one hour for the Budget . . .

(Interruptions)

SHRI BHUPESH GUPTA : Is it a bargain ? Sir, it is a bargain with us.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : No, it is not a bargain.

SHRI BHUPESH GUPTA : Thera should be a parliamentary procedure,,•

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I'lsise sit down. Do not interrupt . . .*(Interruptions)* . . . Pleaded do not interrupt.

SHRI BHUPESH GUPTA : . . subject to the requirenients of reasonable discussion.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I did not say 'Preventive Detention'.

J SHRI BHUPESH GUPTA : These are fraudulent Acts. They bring them forward by changing their names. Therefore, you ar£ right that way. This is the Preventive Detention Act, but hypocritically and fraudulently it has been brought back as the Maintenance of Internal Security Bill. You said, I want to delay. I not only want to de!:iy it, but . . .

(Interruptions)

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I said you want to detain the House.

[SHRI PITAMBER DAS : In order to avoid detention.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Please sit down.

^JI-IRI BHUPESH GUPTA : Then, in two |minutes you pass this and adjourn the House *sine die.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN : All right; Mr. Misra.

श्री एस० डी० मिश्र : श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि यह कोई खुशी की बात नहीं होती कि किसी राज्य सरकार के बजट के सम्बन्ध में यहां इस तरह से चर्चा करे जैसे कि दो तीन साल में होता आ रहा है, कई राज्यों में प्रेसिडेन्ट रूल हुआ और बजट पास करने और उस पर चिन्तन करने का हमें मौका मिलता है, तो उसकी हमें कोई खुशी नहीं होती। वह एक बड़े दुःख की बात है हमारे प्रजातन्त्र के लिये, हमारी डेमोक्रेसी के लिये और जिस ढंग से हमारा फेडरल स्ट्रक्चर धीरे-धीरे इरोड हो रहा है, उसका एक संकेत यह लग रहा है। अभी दो तीन सालों में हमने देखा कि लगभग पांच, छः राज्यों में प्रेसिडेंट रूल हुआ और बराबर इस सदन में और दूसरे सदन में इस पर चर्चायें हुई रूल के बारे में, नियमों के बारे में हमें विचार करने का मौका मिला, फिर बजट पर विचार करने का मौका मिला, वैसे ही पंजाब के संबंध में वही दुखद कहानी हमारे सामने प्रस्तुत है। दुखद कहानी यों है कि आज पंजाब सरकार गिरी और कोई सरकार आवे उसकी कोई बात हीं है। अभी दूसरा मध्यावधि चुनाव होने वाला है और यह निश्चय नहीं है कि मध्यावधि चुनाव के बाद फिर सरकार की शक्ल क्या होगी। उधर से कह दिया जाता है कि युनाइटेड फ्रन्ट्स या संविद सरकारों का कहीं कोई मेल नहीं है, वह हम नहीं चाहते हैं—ऐसा कांग्रेस (आर) के लोग कहते हैं। आज भी इसके अलावा, तीन चार सरकारें करीब-करीब संविद के रूप में काम कर रही हैं—केरल की सरकार संविद के रूप में काम कर रही है, वेस्ट बगाल की सरकार संविद के रूप में काम कर रही है, बिहार की सरकार भी कर रही है और उड़ीसा की सरकार भी करीब-करीब संविद के रूप म काम कर रही है जहां पर संविद दूसरे दलों का हो वह तो सविद खराब हो जाता है, लेकिन जहां कांग्रेस (आर) के साथ मिली हुई सरकारें हो जाती हैं, तो बड़ी स्वच्छ और अमृतमय हो जाती हैं।

हमने दो, तीन वर्षों से डिफेक्शन्स का इतिहास देखा। हमने देखा जब चौधरी चरण सिंह चोली और दामन के रिश्ते के साथ कांग्रेस के साथ चल रहे थे, तब तो बहुत सोशलिस्ट बन गए और ज्यों ही चरण सिंह कांग्रेस (आर) से फट गए या कांग्रेस (आर) से अलग हो गए, त्यों ही वह रिएक्शनरी हो गये। हमने वह दिन भी देखा जब चरण सिंह ने असेम्बली का डेट दिया और कहा अमुक तारीख को असेम्बली बुलाई जायेगी, मैं असेम्बली फेस करूंगा और ज्यों-ज्यों असेम्बली के दिन आते गए, चरण सिंह के ऊपर मुसीबत आती गई और उन्होंने

[श्री एस० डी० मिश्र]

यह बयान दिया कि 24 घंटे के अन्दर चाहे तो असेम्बली बुला लीजिए और केवल 4 दिन असेम्बली के रह गए जब फिर से बुलाई गई, डेट बदल गई—मुझे याद नहीं वह क्या थी—और हमने देखा कि माननीय गवर्नर साहब उत्तर प्रदेश ने उस असेम्बली को ससपेंड कर दिया, मुअत्तल कर दिया और. . .

श्री महावीर त्यागी : जब समन कर लिया था ;

श्री एस० डी० मिश्र : समन की हुई असेम्बली को मुअत्तल कर दिया । और वह दिन भी हमने देखा कि इन कांग्रेस (आर) के बड़े-बड़े नेताओं ने क्या नहीं तारीफ की गवर्नर की, कि बहुत अच्छा उन्होंने सलूक किया, बहुत अच्छा फैसला किया और यह कहा कि गवर्नर का तो डिसक्रीशन है, वह फाइनल होता है हम उसमें कैसे दखल दे सकते हैं । वह तो पब्लिक ओपीनियन का प्रेशर हुआ, महीने दो महीने में सभी विरोधी दलों ने आवाज उठाई और गवर्नर साहब को अपनी राय रिवाइज करनी पड़ी । तो वह भी इतिहास हमने देखा । आज यह इतिहास देख रहे हैं कि माननीय मन्त्री जी आ रहे हैं अप्रूवल के लिए, अप्रूवल ले रहे हैं, लेकिन गवर्नर के कांडक्ट का डिस्अप्रूवल कर रहे हैं । क्या यह सरकार है ? कोई सरकार, अगर उसको लज्जा होगी, और वह अप्रूवल के लिए आयेगी तो टोटल अप्रूवल के लिए आएगी, यह नहीं कहेगी कि गवर्नर का अच्छा होता, अगर गवर्नर साहब इसको न करते । उसके मानी क्या हैं ? उसके मानी केवल यह हैं कि माननीय मन्त्री जी इस प्लेटफार्म से डिस्अप्रूव कर रहे हैं गवर्नर के कांडक्ट को । अगर चरण सिंह के सम्बन्ध में किसी एक गवर्नर का, देश के सबसे बड़े राज्य के गवर्नर का, कांडक्ट ठीक था उस समय, तो आज जो वर्तमान गवर्नर हैं, उनके कांडक्ट के बारे में सरकार को कहना चाहिए था कि हम अप्रूव करते हैं । लेकिन क्यों नहीं करते ? क्योंकि वहां स्वार्थ लिपटा हुआ है; क्योंकि उन्हें आशा थी कि डिसक्रीशन के जरिए जैसा कि उन्होंने पांच, छः प्रदेशों में कराया है वैसे ही डिसक्रीशन के जरिए सत्ता का मजा ले लेंगे । एक तो केन्द्र में डिफेक्शन हुआ—श्रीमती गांधी डिफेक्शनों की नेता हैं, फिर वह डिफेक्शन राज उन्होंने कायम किया, फिर डिफेक्शन राज मैसूर में किया, गुजरात में किया, हरियाणा में किया । एक-एक दिन में, एक-एक हफ्ते में एक-एक एम०एल०ए० सात-सात बार इधर गया, उधर गया । वह भी इतिहास लिखा हुआ है ।

आज डिफेक्शन के बिल के संबंध में मुझे बड़ा दुःख हुआ, जब पन्त जी ने कहा—सचमुच में मुझे दुःख हुआ कि साहब, अपोजिशन के लोग इसमें यूनाइटेड राय दें तब सोचेंगे । इसमें कमेटी बनी, रिपोर्ट हुई । कम से कम आप रिपोर्ट को इम्पलीमेंट करें । कौन सी पार्टीज अपोजिशन की इसका विरोध कर रही हैं ? श्री श्याम नन्दन मिश्र जी, जो इस सदन में विरोधी दल के नेता रहे हैं और इस समय उस सदन में हैं, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी और उसमें हमने कहा था कि कम से कम जो इसमें डिफेक्शन कमेटी की रिपोर्ट है उसको तो आप को इम्पलीमेंट करना ही चाहिए, बल्कि उससे भी अधिक होना चाहिए, कि जो डिफेक्शन करे एम०एल०ए० या एम०पी०, उसकी मेम्बरशिप आटोमेटिकली सीज कर देनी चाहिये । लेकिन हमने सुना क्या है ? श्रीमन्, सही बात तो यह है कि डिफेक्शन लॉ इसलिए इम्पलीमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि एक बड़ा भारी कुअल जोक और मजाक हो गया है और वह यह है कि कांग्रेस (आर) के जो मिनिस्टर हैं वे कहते हैं कि डिफेक्शन बिल लायेंगे । तो यह एक बड़ा मजाक लगता है और हम लोगों को क्यों लगता है ? क्योंकि ये लोग पूरी कहानी सब जगह करके तब इस तरह का डिफेक्शन बिल लाना चाहते हैं । ये लोग सब जगह डिफेक्शन कराके

सब जगह अपना राज्य स्थापित करके, तब इस तरह का डिफेक्शन बिल लायेंगे ।

एक माननीय सदस्य : क्या आप वेट कर रहे हैं ।

श्री एस० डी० मिश्र : हम क्या वेट कर रहे हैं । न तो हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार है और न ही यहां पर हमारी सरकार है । हमारी सरकार कहीं भी बाकी नहीं है । मैं श्री याजी साहब को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उन्हें समझ नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं समझदारी की बात कह सकता हूं ।

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि यह सरकार डिफेक्शन लॉ तब ही लायेगी, जब हर प्रदेश में डी०एम०के० को छोड़ कर, यह हर जगह पर डिफेक्शन लाद देगी और यह करीब-करीब लाद चुकी है । एक दो स्टेट्स जो अभी बाकी बच्चे हैं, वे उनके ही राज्य हैं और उन का सवाल ही क्या है । तो ऐसी सूरत में अपनी बदनीयत को दूसरों पर मढ़ना और यह कहना कि अपोजीशन एक्ट नहीं करता है और इसी लिए डिफेक्शन बिल नहीं लाया जा रहा है, बहुत ही अनुचित बात है ।

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में हमें जो मालूमात हैं वह बड़ी ही दुखद है । डिफेक्शन बिल यह सरकार इसलिए नहीं लाना चाहती है, क्योंकि कमेटी ने जो कुछ कहा है और जिसको अपोजीशन वालों ने सपोर्ट किया ', उन बातों को यह सरकार नहीं लाना चाहती हैं । मालूम तो मुझे यह हुआ है और मेरी मालूमात सही है या गलत है, जैसा कि एक मिनिस्टर ने कहा है उसके आधार पर मैं यह कहना चाहता हूं कि डिफेक्शन बिल केवल यह आने वाला है कि जो एम०एल०ए० और एम०पी० डिफेक्ट कर जायेगा, उसको साल भर के लिए मन्त्री नहीं बनाया जायेगा । यह क्या मजाक है । यह क्या एडल्टरेशन है, क्या मिलावट है, क्या सजावट है ? किस चीज को मिला करके उन्होंने क्या सजावट की हैं । ये कांग्रेस (आर) के मन्त्री लोग भी मिलावट करना चाहते हैं । माननीय नेता श्री दीक्षित जी यहां पर इस समय नहीं हैं । मैं उनके संबंध में उनकी अनुपस्थित में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन इस समय मौका मिल रहा है, इसलिए कह देना चाहता हूँ । श्रीमन्, उन्होंने लोक सभा में कह दिया कि अब इस राज्य में मिलावट कम हो गई है । यह बात उन्होंने उस सदन में कही कि मिलावट कम हो गई है । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस राज्य में अगर कोई सबसे बड़ी चीज है तो वह मिलावट ही है । आज हर चीज में एडल्टरेशन है, यहां तक कि प्रिंसिपल में भी एडल्टरेशन है । उन्होंने कहा कि घी और दूध पर एडल्टरेशन कम हो गया है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि वह जो बिल डिफेक्शन के सम्बन्ध में ला रहे हैं, उसमें वह मिलावट करके ला रहे हैं ।

सरकार डिफेक्शन लॉ के सम्बन्ध में कहती है कि आज ला रहे हैं, कल ला रहे हैं । पिछले साल भी इस सरकार ने कहा था कि हम जल्दी डिफेक्शन बिल लायेंगे, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि वह इस साल भी नहीं लायेगी और इस सैशन में भी नहीं लायेगी; क्योंकि एक आध जगह और बाकी बच गये हैं, जिनको वह पूरा करना चाहती है और उसके बाद ही वह इस तरह का डिफेक्शन बिल लाना चाहती है । बिल भी जो लायेगी उसमें केवल यही होगा कि एम० एल० ए० और एम०पी० साल भर तक मिनिस्टर नहीं रह सकेंगे ।

श्री महावीर त्यागी : साल भर के बाद तो मिनिस्टर होंगे ।

श्री एस० डी० मिश्र : साल भर तक तो नहीं हो सकते हैं और एक साल के बाद हो सकते हैं । श्रीमन्, आया राम, गया राम के नेता, श्री चव्हाण साहब रहे हैं, कम से कम उन्होंने ही यह शब्द दिया आया राम, गया राम । उन्होंने एक जगह रहते हुए, एक ही पार्टी में

[श्री एस० डी० मिश्र]

रहते हुए आया राम, गया राम, स्वयं हो गये थे वे। एक बार उन्होंने सिंडिकेट कांग्रेस का साथ दिया और फिर उसी समय, उसी जगह पर मिलावट खाकर इन्डीकेट में हो गये। उन्होंने आया राम और गया राम के खिलाफ बड़ी आवाज उठाई थी और देश को बड़ी आशा बंधी थी लेकिन वह आशा अब निराशा में बदल गई है।

हमारे पन्त जी बड़ी मौरेलिटी की बात करते हैं। पन्त जी ने अपने पिता जी से केवल एक ही सबक सीखा है, एक ही चीज सीखी है। मौरेलिटी सीखी है या नहीं सीखी है, मैं नहीं जानता हूं। हमारे पन्त जी के पिता जी जो थे वे जब आरग्यूमेंट करते थे तो उसकी बाल की खाल नहीं निकालते थे। वे सफाई से बात करते थे, लेकिन हमारे पन्त जी बाल की खाल निकालते हैं और सैटिसफेक्शन नहीं देते हैं। एक आध गुण पिता जी के ले लेते और एक आध गुण नहीं लेते। मुझे उनके पिता जी से पूरा भरोसा था कि अगर वे होते तो डिफेक्शन के बिल को फौरन ले आते और कमेटी ने इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, उससे भी ज्यादा रिगोरस से इसको बनाते। लेकिन आज यह सरकार दूसरों पर दोष लगा कर डिफेक्शन के बिल को नहीं ला रही है। तो आज यह ट्रेन्ड है जो पंजाब में हुआ है। यह पंजाब तक ही सीमित नही है, देश भर में ऐसा है। अभी 60 लाख रुपया निकाला गया स्टेट बक से। लोग कहते हैं कि वह केवल इसलिए निकाला गया कि बिहार में उसका खर्चा किया जाय। आज रुपया खर्च करके कांग्रेस (आर) डिफेक्शंस करा रही है। अगर ऐसा नहीं है तो उसको सामने आना चाहिए...

श्री शीलभद्र याजी (बिहार) : गलत है।

श्री एस० डी० मिश्र : याजी साहब जो बागड़ बिल्ला की तरह बार-बार उठ रहे हैं, मैं सुन नहीं पा रहा हूं कि वे क्या कह रहे हैं। (*Interruption*) वे सीट पर उठते हैं, कुछ कहते हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कह रहे हैं।

तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि आज जो दुर्भाग्य है पंजाब का उसको आप देखें...

SHRI B. K. KAUL (Rajasthan) : I feel the word *bagar billa* is no parliamentary ; it should be expunged.

श्री एस० डी० मिश्र : बागड़ बिल्ला के माने एक खिलौना के हैं। (*Interruption*) बागड़ बिल्ला एक खिलौना होता है जो ऊपर जाता है, नीचे जाता है। उसमें डिलीट करने की कोई बात नहीं है।

(*Interruption*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Order, order please. Will you conclude now ?

SHRI S. D. MISRA : I will continue after lunch ; I will take about 10-15 minutes ; I must come to the budget side of it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The House stands adjourned till 2.00 P.M.

The House adjourned for lunch at two minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at two of the clock, THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) in the Chair.

श्री एस० डी० मिश्र : श्रीमन्, अवकाश के पहले मैं यह बात कह रहा था कि इस देश में किस प्रकार आयाराम, गयाराम को इज्जत दी गई है और वह किसकी जिम्मेदारी है। आज गवर्नर पंजाब ने जो कुछ किया है, वह उन्होंने अपने जो अधिकार हैं उनका प्रयोग करते हुए किया है। आज कल 174 आर्टिकल जो कांस्टीट्यूशन में दी गई है, जब तक उसमें तरमीम न हो तब तक गवर्नर को पूरा अधिकार है, उसका

सोल डिस्क्रिशन है कि वह असेम्बली को डिजाल्व करे या न करे। मैं तो गवर्नर पंजाब को बधाई देता हूं कि उन्होंने सिक्रेट इंस्ट्रक्शन्स सेंटर से नहीं लिए और दुर्भाग्य की बात है कि आज बहुत से गवर्नर्स सीक्रेट इंस्ट्रक्शन्स लेते हैं सेंटर से। तो जिस बात में गवर्नर को सोल अधिकार हैं, उसमें अगर पंजाब के गवर्नर ने सीक्रेट इंस्ट्रक्शन्स नहीं लिए तो उनको बधाई ही दे सकता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि पंजाब के गवर्नर पावटे साहब को रिकाल होना चाहिये। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। रिकाल इस बात पर नहीं हो सकता; क्योंकि उन्होंने अपने पद का और अपने अधिकारों का सही मानों में और मर्यादापूर्वक पालन किया है और जो अधिकार विधान द्वारा उनको दिये गये हैं, उनका उन्होंने प्रयोग किया है। इसलिए सही बात तो श्रीमन्, यह है कि आज समय आ गया है कि गवर्नर्स की पावर्स के सम्बन्ध में कोई गाइड लाइन्स होनी चाहिये और कांस्टीट्यूशन में उसका विधान होना चाहिए। आज सेंटर स्टेट रिलेशनशिप खतरे में है। उस पर भी विचार होना चाहिए। आज सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में गवर्नर्स आते हैं, उनके क्या अधिकार होना चाहिए यह भी तय होना चाहिए। लेकिन यह गाइड लाइन्स केवल गृह मन्त्रालय या सेंट्रल गवर्नमेंट जो दे दे वही नहीं होनी चाहिये, इन पर सभी पार्टियों में विचार हो और फिर कांस्टीट्यूशन में यह बात आये। सभी दलों के लोग उस पर विचार करें; क्योंकि तीन वर्ष पहले जो कहानी थी कि ज्यादातर एक दल की सरकार सब जगह थी वह स्थिति आज नहीं हैं, हालांकि डिफेक्शन्स के जरिये आज वह स्थिति लायी जा रही है, लेकिन जो हालत भविष्य में होने वाली है वह यह है कि केंद्र में किसी दल का शासन हो सकता है और प्रान्तों में किसी और दल का शासन हो सकता है। कभी हमने यह उम्मीद नहीं की थी कि केन्द्र में एक दल का शासन होते ही उसका दुरुपयोग किया जायेगा और जो दल दूसरे दलों के साथ हैं, उन में डिफेक्शन्स करा कर उन पर इस तरह से प्रहार किया जायगा। तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के सम्बन्ध में, गवर्नर्स के अधिकारों के सम्बन्ध में, उनके प्रयोग के सम्बन्ध में पूरे तौर से विचार होना चाहिये और गाइड लाइन्स का मतलब यह नहीं है कि जो प्रधान मंत्री जी या होम मिनिस्टर कह दें वही गाइड लाइन्स हो जाए। तमाम पार्टियों द्वारा उस पर विचार होने के बाद वह गाइड लाइन्स तय होनी चाहिये।

एक बात और कह कर मैं इस सम्बन्ध में अपनी बात खत्म करूंगा। मुझको जहां तक स्मरण है श्री लक्ष्मण सिंह गिल भी मुख्य मंत्री थे कुछ दिन के लिए और उनको इसी कांग्रेस (आर) वालों ने डिफेक्ट कराया, लेकिन फिर उन को वे मुख्य मत्री नहीं बना सके और अब गुरुनाम सिंह गिल के 17 आदमियों को लेकर कांग्रेस(आर)वाले डिफेक्ट करा रहे थे। तो इन के सम्बन्ध में वे कहते हैं कि करप्ट हैं, गिरा हुआ है और मैंने अखबारों में भाषण देखने की चेष्टा की, बड़ा खराब एडमिनिस्ट्रेशन है, यह कमी है, वह कमी है, उसमें सेकुलरिज्म नहीं है। तो जब आप लक्ष्मण सिंह गिल को लेना चाहते हैं तो वह सेकुलर हो जाते हैं, और जब गुरुनाम सिंह को पा जाते हैं तो वे सेकुलर हो जाते हैं, और अगर उनको नहीं पाते तो वे कम्युनल रह जाते हैं। आज कम्युनल पोलिटिक्स का गौरव बढ़ाने वाली कौन है, आज डी० एम० के० की पोलिटिक्स, अकाली की पोलिटिक्स, मुस्लिम लीग की पोलिटिक्स का गौरव बढ़ाने वाली कौन है ? आज की केन्द्र की सरकार है। मैं आपसे कह रहा हूं कि केन्द्र की सरकार है।

और करप्शन की बात कहते हैं। कहा जाता है कि बादल की सरकार बड़ी करप्ट थी, इसलिए गिर जानी चाहिये थी। अगर करप्शन की बेसिस पर किसी सरकार को जाना चाहिये तो केन्द्र की सरकार को सबसे पहले जाना चाहिये। हमने इसको लाइसेंस के मामले में

[श्री एस० डी० मिश्र]

देखा है, हमने चुनाव के समय में देखा है और 60 लाख रुपये की कहानी देश देख रहा है, हो सकता है कि इसका भंडाफोड़ हो, हो सकता है कि इसको छिपाया जाय। तो अगर करप्शन की बेसिस पर किसी सरकार को जाना है तो आज की केन्द्र की सरकार को जाना है, जिसने करप्शन को गौरव दिया है, रेसपेक्टेबिलिटी दी है। जब केन्द्र में इस तरह का करप्शन हो तब प्रान्तों के सम्बन्ध में कहा जाय कि गिल मिल या कौन-कौन या बादल या छोटे-छोटे मुख्य मंत्री करप्ट हैं। आज तो जमाना आ गया है कि किसी तरह से चन्दा ले कर रखो। चुनाव के खर्चे एक-एक या दो-दो लाख देने होंगे उसी की बुनियाद पर सभी रखेंगे, चाहे स्टेट बैंक में रखें, चाहे ट्रेजरी में रखें, लेकिन लेकर रखना है। तो जब यह रखने की हालत हो गई है, जब करप्शन इस तरह से हो रहा है तो केवल करप्शन की बुनियाद पर यह मांग करना कि बादल की मिनिस्ट्री खराब थी।

श्री शीलभद्र याजी : आप भी कांग्रेस के मंत्री थे, कौन सी तिजोरी में रखा।

श्री एस० डी० मिश्र : बैठ जाइये। दो आदमी बोलेंगे या एक आदमी बोलेगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : याजी जी, आप बैठ जाइये।

श्री एस० डी० मिश्र : पंजाब हमारा एक बार्डर स्टेट है और आप जानते हैं कि रेट आफ ग्रोथ की दृष्टि से, इकानामी में रेट आफ ग्रोथ के हिसाब से, चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे इंडस्ट्री का हो, वह बहुत अच्छा है, कम्पेरेटिवली अच्छा है, जब कि हमारी 5 परसेंट रेट आफ ग्रोथ है, तब पंजाब की एग्रीकल्चर की 8 परसेंट है और 7 या साढ़े 7 परसेंट इंडस्ट्री की रेट आफ ग्रोथ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज वहां का किसान रो रहा है, जहां का एग्रीकल्चरिस्ट बहुत खुशहाल था, वहां आज पंजाब का किसान सचमुच में रो रहा है। वही हालत हरियाणा की है, लेकिन चूंकि हरियाणा की चर्चा नहीं, इसलिये उसके बारे में नहीं कहूँगा। वही हालत यू० पी० की है और पूरे उत्तर भारत की है और शायद दक्षिण भारत की भी है। लोगों में यह भ्रम छाया हुआ है कि किसान खुशहाल होता जा रहा है, खुशी होता जा रहा है। श्रीमन्, आज पंजाब का किसान बिलकुल रो रहा है। क्यों रो रहा है? सरकार के टैक्सेज की वजह से, चाहे ट्रैक्टर हो चाहे फर्टिलाइजर हो, कोई भी चीज हो, सरकार के टैक्सेज बढ़ते चले जा रहे हैं, इनपुट्स की प्राइसेज बढ़ती चली जा रही हैं और उसको अपने प्रोडक्शन की रेम्युनेरेटिव प्राइस नहीं मिल रही है। आज जरूरत इस बात की है कि पंजाब के किसानों को न केवल रेम्युनेरेटिव प्राइस दी जाय, बल्कि रेम्युनेरेटिव पैरिटी प्राइस दी जाय। पहले यह होता था कि गल्ले का दाम बढ़ता था तो और चीजों के दाम भी बढ़ते थे और अगर गल्ले का दाम घटता था तो और चीजों का दाम भी घटता था। लेकिन दो साल से मैं देख रहा हूं, इस देश के आर्थिक इतिहास की कहानी यह हो रही है कि और चीजों के दाम बढ़ते हैं और गल्ले के दाम घटते हैं, अगर घटते नहीं हैं तो कम से कम बढ़ते तो नहीं हैं। आज तो यह हालत है कि उत्तर प्रदेश की मंडियों में गल्ला कोई लेने वाला नहीं है। फूड कार्पोरेशन चाहे खरीद लेता हो तो खरीद लेता हो, लेकिन गेहूं वहां पैदा हुआ है और उसको लेने वाले लोग नहीं हैं। तो आज पंजाब का किसान रो रहा है। उसके पास पावर नहीं है, पंजाब में पावर कट इतना है कि रोज ही वह बढ़ता जाता है और किसानों का प्रोडक्शन और फैक्ट्रीज कम ही होती जा रही हैं। इसीलिये कहा गया कि एक न्युक्लीयर पावर स्टेशन पंजाब में होना चाहिये, एक उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, बल्कि नार्थ में दो तीन होना चाहिये। तो क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि बजट में कितना रुपया पावर के लिये प्रोवाइड किया है, कम से कम

सौ करोड़ या पचास करोड़ रुपया प्रोवाइड होना चाहिए केवल पंजाब के लिये पावर की मद में, जिससे कि वहां कम से कम पावर कट नहीं हो और वहां किसानों का प्रोडक्शन बढ़े। लेकिन मैंने बजट में देखने की कोशिश की तो उसमें थोड़ा सा जरूर है जैसा कि हर प्रदेश में 25 या 30 लाख होता है, उसी तरह से इसमें कुछ न कुछ रखा है, लेकिन पंजाब जहां कि इतनी प्रगति हुई है वहां पावर के लिये तो रुपया अधिक होना चाहिये। तो मैं समझता हूं कि इसमें इसके लिए अधिक करना चाहिये।

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : अब आप मेहरबानी करके खत्म करें।

श्री एस० डी० मिश्र : जी हां, मैं कर रहा हूं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा। श्रीमन्, यह तो प्रेसीडेन्ट रूल है। कुछ ही समय बाद चुनाव होंगे और होने भी चाहिएं। चुनाव जिस तरह से हो रहे है—आप सहमत हों या न हों, कुछ लोग सहमत हों या न हों—उसके सम्बन्ध में काफी चर्चायें हुई, विवाद हुये और इलेक्शन कमिश्नर के सम्बन्ध में भी बड़ी चर्चायें हैं। बहुत विवाद हैं, लोगों का खयाल है कि वह अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। नियम न ढंग से बन रहे हैं, न ठीक से पालन हो रहा है। और खास तरह से इलेक्टोरल रौल जिस तरह से जल्दी में, रश में बनाए जाते हैं, उसमें तरमीमें होती हैं, वह एक दुर्भाग्यपूर्ण कहानी है। चुनाव होने से पहले इलेक्शन कमिश्नर को देखना चाहिए कि इलेक्टोरल चेन्जेज जो होने हैं वे पूरे ढग से हों, उनमें नियम का परिवर्तन होना है तो तत्काल न हो, जैसे कि इस बार चुनाव हुआ 27 तारीख को नामिनेशन होता है और 25 ता० को सेन्ट्रल गवर्नमेंट का गजेट नोटिफिकेशन हो जाता है कि इस तरह से काउंटिंग होगी, इस तरह से प्रोसीजर होगा। इस तरह का एक यूनीलेटरल डिसीजन हो गया। मैं तो यह मांग करूंगा कि अब मध्यावधि चुनाव इसका आ रहा है। 1972 में चुनाव करीब-करीब हर प्रदेश में होने वाला है और मुझे कोई शक नहीं कि यू० पी० और बिहार में स्वयं कांग्रेस (आर) वाले आपस में लड़ कर यू० पी० और बिहार में चुनाव कराएगे। एक दो स्टेट्स को छोड़ दीजिये, हमारा तो अनुमान है केवल मद्रास और तमिल नाडु को छोड़ कर हर जगह 1972 में आम चुनाव होंगे। और अगर चुनाव होना है तो स्वच्छ प्रणाली के लिये, नियमों का संशोधन करने के लिए, नियमों को कार्यान्वित करने के लिए वह जो वहां बन मैन इंडिपेन्डेन्ट इलेक्शन कमीशन की बात है उसको स्क्रैप करना चाहिए, आज थ्री-मैन इलेक्शन कमीशन होना चाहिये, जिसमें ऐसे लोग हों जिनका स्टेटस हाई कोर्ट जज के बराबर हो। ऐसे लोग न हों जो बराबर प्रतीक्षा में हैं सरकार की कि कहां उनकी पोस्टिंग हो रही है, कहां वह अम्बेसेडर और गवर्नर बनाये जा रहे हैं।

(*Interruption*)

तो श्रीमन्, अन्त में मैं इतना ही कहूंगा कि जो मैंने डिफेक्शन्स के सम्बन्ध में कहा है और इलेक्शन कमिशनर के सम्बन्ध में कहा है—इसमें पोलिटिकल मोटिवेशन की बात नहीं है—बजट के संबन्ध में मैंने कहा है कि ये चीजें ऐसी हैं जिन पर सरकार को विचार करना चाहिये और वह एक आईना ऐसा अपने सामने रखें, जिससे अपना प्रतिबिम्ब दीखे। चेहरा सुन्दर जरूर है, लेकिन कभी-कभी आईना सामने रखलें तो धुंधला चेहरा जो दिखाई दे रहा है पंत जी की औरों को. . .

श्री शीलभद्र याजी : जैसे आपका चेहरा हमको दीख रहा है।

श्री एस० डी० मिश्र : तो अगर थोड़ा सा अपना चेहरा कभी यह देख लें तो समझ में आ जाएगा कि उनकी शक्ल और लोग कैसी देख रहे हैं। सारा हिन्दुस्तान देख रहा है। उनका जो नया नारा गरीबी हटाओ का है, वह पंजाब में हटा दें, अब तो वहां सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है। हम आशा करते हैं वहां के जो एम्प्लाईज

[श्री एस० डी० मिश्र]

है उनकी तकलीफों को दूर करेंगे। इस बजट को जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, इसमें मैंने देखा नान गजेटेड आफिसर्स जिनके पे स्केल्स का सवाल है, उनके लिये एक पैसा नहीं रखा। इसी तरह से पे स्केल आफ टीचर्स का सवाल था, कोई पैसा नहीं रखा।

इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं, ऐसा बजट सरकार ने लाना था तो अपनी तसवीर स्वयं देख लें हम लोग क्यों दिखाएं।

श्री मान सिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश) : उप-सभाध्यक्ष महोदय, आज ही राष्ट्रपति की घोषणा के सम्बन्ध में हुई बहस का उत्तर देते समय माननीय पंत जी ने इस बात को स्वीकार किया कि पंजाब ऐसा प्रदेश है कि जहां पर बराबर ही सांप्रदायिकता की भावना रही है और उसके कारण से वहां पर बराबर समस्यायें उपस्थित होती रही हैं। ठीक बात है यह। उन्होंने इसको स्वीकार किया है। परन्तु श्रीमन्, इसके सम्बन्ध में मुझे यह पूछना है कि वहां पर सांप्रदायिकता बढ़ी है, कम नहीं हो सकी, यह किसका दोष है? यह दोष कांग्रेस सरकार का है जिसके कारण वहाँ पर साम्प्रदायिक भावना पनपी है और उसे प्रोत्साहन मिला है। आज से 30-40 वर्ष पहिले की बात है कि वहां पर हिन्दुओं और मुसलमानों का इतना सवाल नहीं था जो सवाल हिन्दुओं और सिखों का वहां पर आज पैदा कर दिया गया है। आखिर क्या हिन्दू सिखों से अलग हैं? सिख शब्द जो है वह शिष्य से बना है। शिष्य, गुरू से पैदा हुए। गुरू किस लिए पैदा हुए? गुरुओं का जन्म किस वास्ते हुआ? गुरुओं का जन्म हिन्दुत्व की रक्षा करने के लिए हुआ था। हिन्दुत्व की रक्षा करने के लिए गुरुओं ने जन्म लिया। आज जो उनके अनुसरण करने वाले हैं, जो उनके फोलोवर्स हैं उनकी भावना ऐसी हो गई है कि हम हिन्दुओं से अलग है और इस तरह की भावना को बल किस से मिला? इनकी कृपा से जो उधर बैठे हैं।

(*Interruptions*)

एक माननीय सदस्य : यह तो अंग्रेजों की कृपा से हुआ।

श्री मान सिंह वर्मा : आप तो उनके दत्तक पुत्र हैं। तो मैं यह कह रहा था कि आज से 40 वर्ष पहले देश के अन्दर जो साम्प्रदायिक भावना थी, उसका अन्दाजा लगाइये। और जब से आजादी आई, उसके पश्चात जो साम्प्रदायिकता देश के अन्दर प्रबल हुई है, उस का अन्दाजा लगाइये, तो आपको मानना पड़ेगा कि साम्प्रदायिक भावना को किस ने पैदा किया है।

अभी माननीय कौल साहब ने कहा कि अंग्रेजों की यह देन थी। ठीक है, परन्तु स्वतंत्रता के पश्चात जो अंग्रेजों की गलत देन थी उन्हें समाप्त कर दिया जाना चाहिये था। देश स्वतंत्र हो गया है और अपने लोगों द्वारा यहां पर राज्य होने लगा है, प्रशासन अपने द्वारा चलाया जा रहा है, तो फिर इस तरह की जहरीली भावना को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने तो अंग्रेजों के गुरुमंत्र को संजोकर रखा है और उससे लाभ उठाया है; अंग्रेज भी डिवाइड एन्ड रूल की नीति अपनाते थे और हम भी उसी नीति को अपना रहे हैं। आज तक पंजाब के अंदर जो खेल होता रहा है वह इसी बात के लिए हुआ है।

एक सिख परिवार है, वह केश रखता है मगर उनकी रिश्तेदारियां नान केश धारियों के यहाँ हैं, दूसरों के यहां है और इस तरह से बराबर के रीति रिवाज, खानपान और शादी ब्याह एक दूसरे से हुआ करते थे। लेकिन गुरू ग्रन्थ साहब और गुरू नानक साहब के प्रति सब की श्रद्धा थी, सब हिन्दुओं की श्रद्धा थी। आज भी है। वहां पर पहिले भाषा का झगड़ा नहीं

था और वह झगड़ा तब से शुरू हुआ जब से वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी। इसी सरकार के कारण वहां पर तरह तरह के झगड़े हुए।

कांग्रेस कहती है कि हम सिक्यूलरिज्म को मानते हैं, धर्मनिर्पेक्षता को मानते हैं। धर्म-निर्पेक्षता के माने यह नहीं हैं कि जो कर्त्तव्य परायणता है उसको समाप्त कर दिया जाये।

श्रीमन्, पंजाब के लिए यह विशेष बात रही है और इसी कारण पंजाब का विभाजन हुआ। पंजाब का विभाजन किस की देन है? पंजाब का विभाजन भी इन्हीं की देन है और पंजाब के विभाजन के पश्चात हमेशा इस बात की कोशिश करते रहे कि इस सरकार को गिराना है, उस सरकार को गिराना है। जहां पर अपना प्रभुत्व है वहां पर सरकार रहेगी और जहां पर अपना प्रभुत्व नहीं होगा वहां सरकार गिरा दी जायेगी।

श्रीमन, डिफेक्शन सम्बन्धी बिल के लिए कितने दिनों से माननीय सदस्य सरकार का ध्यान दिला रहे हैं। डिफेक्शन कब ही का बन्द हो जाता लेकिन यह सरकार बन्द करना नहीं चाहती है। आज इस सरकार को यह कहते कितने दिन हो गये कि हम डिफेक्शन के लिये बिल ला रहे हैं। डिफेक्शन उस समय तक बन्द नहीं हो सकता है जब तक कि उसके अन्दर यह प्रावधान नहीं किया जाता है कि अगर एक पार्टी से कोई दूसरी पार्टी में चला जायेगा तो उसको मेम्बरशिप छोड़नी पड़ेगी, उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, उसको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी और कम्पलसरीली रिजाइन करना पड़ेगा। जब तक ये चीजें इसमें नहीं डाली जाती हैं तब तक डिफेक्शन बन्द नहीं हो सकता है। सरकार इस तरह का बिल ला रही है कि एक साल तक मन्त्री नहीं बन पायेंगे। इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप चार साल तक मन्त्री न बनें और 10 लाख रुपया दे दिया जाय तो फिर मन्त्री बनने की क्या जरूरत है। आप इस तरह से रुपया देकर लोगों को खरीद सकते हैं। अगर आप पद नहीं देंगे तो आप रुपया दे सकते हैं। यह डिफेक्शन उसी समय बन्द हो सकता है जब आप इसमें उस तरह के प्राविजन डालें जैसा मैंने ऊपर बतलाया है। अगर कोई एम० पी० किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो उसको त्यागपत्र देना होगा, अगर कोई एम०एल०ए० दल बदल करता है, तो उसको त्याग पत्र देना चाहिये और अगर वह फिर से आना चाहता है तो दुबारा चुनाव जीत कर आये। अगर इस तरह की बात होगी तो तब ठीक है। लेकिन यह सरकार इस तरह की बात डालने के लिए तैयार नहीं है। इस वास्ते डालने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसकी सारी गाड़ी इसी कारण चल रही है। इस तरह की बातों को देखकर मुझे बड़ा दुख होता है।

श्रीमन्, एक दफा मुझे याद है, कांग्रेस प्रेजीडेंट श्री जगजीवन राम जी ने बड़े अभि-मान और गर्व के साथ यह बात कही थी कि बिहार के कुछ सदस्य टूटकर हमारे पास आ रहे हैं और हमें अब कोई डर नहीं है। लोग टूट करके आते हैं उनको अपनाने में बड़ा गौरव होता है तो जहां पर डिफेक्शन के लिये गौरव का अनुभव हो क्या वहां पर श्रीमन, कभी डिफेक्शन बन्द हो सकता है। नहीं बन्द हो सकता है। तो इस प्रकार से यह साम्प्रदायिकता, इस प्रकार से यह दलबदलना, यह कभी भी दूर नहीं हो सकता क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है वह इस बात का प्रयास करती रहती है कि इस प्रकार से अगर होता रहा तो हम सत्ता में बने रहेंगे।

श्रीमन्, भाषा का प्रश्न है। पंजाब में भाषा का प्रश्न बड़ा जटिल बना दिया गया है। पहले नहीं था। आखिर हिन्दी और पंजाबी में अन्तर क्या है। हमने हमेशा इस बात को कहा है और हम मानते हैं कि सब प्रदेशों से जो रीजनल लैंग्युलेज हैं, जो हमारी क्षेत्रीय भाषायें हैं, अपने अपने स्थान पर सब को उन्नति करन,

[श्री मान सिंह वर्मा]

चाहिये, अपने अपने स्थान पर सब को पनपना चाहिये । जितनी भी हमारी क्षेत्रीय भाषायें हैं वे सब प्राय: संस्कृत से निकली हैं और उनकी मां संस्कृत है और इस कारण से संस्कृटाइज्ड जितनी भी लैंग्युएजेज हैं वे सब अपने अपने स्थान पर तरक्की करें । एक सम्पर्क भाषा जरूर होनी चाहिये और वह हिन्दी मानी गई है । विधान ने भी उसको माना है और बड़े बड़े लोगों ने भी उसको माना है । इसका कोई झगड़ा नहीं था । मैं स्वयं लाहौर में पढ़ा हूं । संस्कृत का केन्द्र रहा है लाहौर 1924, 25 की बात है । मैं आप को बताऊं कि वह जिस प्रकार से संस्कृत का केन्द्र बना हुआ था उससे काशी की याद आ जाती थी । आज जा करके हम देखते हैं कि पंजाब में संस्कृत का कोई नाम लेने वाला नहीं है । संस्कृत महाविद्यालय वहां पर चलते थे । आज़ादी के पश्चात वहां पर संस्कृत का बोल बाला होना चाहिये था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ । वहां ऐसी भावना को प्रोत्साहन दिया गया कि संस्कृत तुम्हारी भाषा नहीं है, हिन्दी तुम्हारी भाषा नहीं है, पंजाबी तुम्हारी भाषा है । आखिर पंजाबी और हिन्दी मे अन्तर क्या है । हिन्दी का एक विकृत रूप पंजाबी है । वह एक डाइलेक्ट है । लोग इस प्रकार से उसको बोलते हैं कि हिन्दी में हम पुत्र कहेंगे, उसमें वे पुत्तर कहेंगे, हिन्दी में हम मित्र कहेंगे और उसमें वे मित्तर कहेंगे। अन्दर केवल बोलने का है । इसमें कोई विशेष अन्तर नहीं है । इसमें इस प्रकार की धार्मिक भावना बढ़ा देना यह कांग्रेस का काम है ।

दूसरे हरिजनों का प्रश्न आया था । हमारे सम्मानित मित्र माथुर जी ने ध्यान दिलाया था माननीय मन्त्री जी का और पन्त जी ने उसका उत्तर दिया था । उन्होंने कहा कि प्रसीडेंशियल रूल में इस बात का प्रयत्न किया जायेगा कि उनके साथ जो भी ज्यादतियां हुई हैं वे नहीं होने पायें । मैं उनके उत्तर से सतुष्ट नहीं हूं । मैं यह चाहता हूँ कि बराबर जो इधर समाचार आये हैं । पंजाब के उन से यह पता लगता है कि बड़े बड़े अत्याचार, बड़े बड़े जुल्म वहां पर हरिजनों के ऊपर पिछले दिनों श्री बादल के समय में हुये हैं । वे अत्याचार किस प्रकार के हैं । उनको जो जमीनें पिछली मिनिस्टरी में दी गई थीं, जो पट्टे लिखवाये गये थे, वे पट्टे वापस ले लिये गये, वे जमीनें उनसे छीन ली गई । गांव गांव में, जगह जगह में स प्रकार के अत्याचार हुए हैं । कहीं गांवों से लोगों को निकाला गया है, कहीं किसी ने मकान बना लिया तो वह मकान उससे वापस लिया जा रहा है । इस प्रकार की वहां पर वारदातें हुई हैं । इसके लिए मैं यह निवेदन करूंगा कि एक इन्क्वायरी कमीशन बैठाया जाये जो इस बात की खोज करे कि पूरे पंजाब में हरिजनों के ऊपर किस प्रकार के अत्याचार हुये हैं और उन का निराकरण करने के लिए वह कमीशन अपनी रिपोर्ट दे ।

तीसरी चीज बहुत संक्षेप में मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत अर्सा हुआ जब 83 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दिया गया था पानी के सिलसिले में । उस रुपये को देने के बाद इतना लम्बा अर्सा हो गया कि पाकिस्तान ने अपने बांध बना लिए, अपनी नहरें बना लीं और जो उसके यहां कमियां थी उन को पूरा कर लिया । किन्तु अभी तक हमारा न तो पोंग बांध पूरा हो पाया और न सतलुज का थीम बांध अभी तक प्रारम्भ हो पाया । उसका नतीजा यह है कि जितना भी हमारा पानी है वह पाकिस्तान के पास जा रहा है । उससे लाभ उठा कर पाकिस्तान ने अपनी संपन्नता बढ़ा ली है । अगर उस पानी का हमारे यहां उपयोग किया जाता तो उससे हमारे यहां बिजली ज्यादा बनती और डैम हमारे पूरे हो जाते । अभी मिश्रा जी ने जिक्र किया था कि बिजली की कमी के कारण किसानों को ऐसी हानि हो रही है कि किसानों को जिस प्रकार से पनपना

चाहिए, उस प्रकार से वे पनप नहीं पाये हैं। मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं।

अब मैं एक और बात कह कर समाप्त कर रहा हूं और वह बात यह है कि मंडियां हमारी समाप्त हो रही हैं। श्रीमन्, आप जानते हैं कि पंजाब जो है वह सारे देश को गेहूं देता है अनाज देता रहा है, ग्रेनरी कहलाता है हमारे देश की। लेकिन वहां पर आज यह स्थिति है कि मंडियां पटी पड़ी हैं और एस०टी०सी० वहां पर उठा नहीं सकी गल्ला। पहले तो कुछ असमय में वर्षा हो गयी उसके कारण गल्ला *खराब हुआ, भूसा खराब हुआ और उसके बाद* जो मंडियों में आया वह उठा कर नहीं ला सके पूरे तरीके से वह वहां खराब हो गया और उसका नतीजा यह है कि वह स्वयं कंट्रोल नहीं कर पाते। और एक भयावनी प्रवृत्ति चल रही है हमारे प्रशासन में आज कि हर चीज को सरकार करेगी। सरकार उस को ठीक प्रकार से कर सके या न कर सके। लेकिन सरकार को करना चाहिए। जबकि दूसरे न कर पा रहे हों किसी काम को और असुविधायें हो रही हों तो सरकार को किसी काम को करना चाहिए, लेकिन स्वयं सरकार करेगी नहीं और दूसरों को करने नहीं देगी और नतीजा यह होगा कि जनता सफरर होगी। छोटे छोटे आदमी, छोटे-छोटे किसान, छोटे-छोटे कर्मचारी जो उसके भरोसे पर जिन्दा रहते हैं, जिनके कारण सारे देश को अन्न मिलता था आज वही बड़े सफरर हैं और जो समाजवादी सरकार है वह उन गरीबों का पेट काट रही है और पेट अगर मोटे हो रहे हैं तो एस०टी०सी० के आफिसर्स के हो रहे हैं। गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि इन मंडियों को क्यों समाप्त किया जा रहा है, छोटे छोटे आढ़तियों को क्यों समाप्त किया जा रहा है। इस प्रकार का प्रतिबन्ध होना चाहिए कि यदि सरकार ने यह भार अपने हाथ में लिया है तो उसको संपन्नता के साथ, योग्यता के साथ करे और ठीक प्रकार से वह होना चाहिए। लेकिन यहां तो न खुदा ही मिला न बिसाले सनम, न इधर के रहे, न उधर के रहे। काम करने वालों को करने न दें और अपने आप करें नहीं। तो इन शब्दों के साथ मैं अपने कथन को समाप्त करता हूं और मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिन बातों की ओर मैंने मन्त्री जी का ध्यान दिलाया है उन पर वे गौर करने की कृपा करें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : Mr. Niren Ghosh.

श्री राजनारायण : *मैं भी बोलूंगा।*

श्री एस० डी० मिश्र : श्रीमन्, एक मेम्बर बोलने खड़े हुए और राजनारायण जी सामने से चले गये, उनको रोका जाये।

SHRI NIREN GHOSH : All parties can speak ; it is a general discussion.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : We will finish the Budget and then we will take up the Appropriation Bill.

श्री राजनारायण : मैं तो इस बजट पर बोलूंगा।

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT/**संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री** (SHRI OM MEHTA) : Sir, only one hour was allotted for this by the Business Advisory Committee.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : I want the hon. Members to know that one hour was allotted for this . . .

श्री राजनारायण : आनरेबिल मेम्बर यह सब कुछ नहीं जानते, वे अपना कर्त्तव्य जानेंगे, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, सरकार के नहीं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : Your representatives have decided in the Business Advisory Committee. . .

श्री राजनारायण : वह बिजनेस कमेटी है, गिलोटिन कमेटी नहीं है । बिजनेस कमेटी सरकार की खिलाऊ कमाऊ नहीं है ।

SHRI NIREN GHOSH : Sir, it is a tragic thing that we are forced to take up the Budgets of different States at different times.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : Mr. Niren Ghosh, we are now dealing with the Budget of Punjab.

SHRI NIREN GHOSH : Yes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : We have discussed the Proclamation for the establishment of President's rule. The Appropriation Bill will come later on. If you want to speak generally, you can speak later on ; 1 will give you time. All right, now Mr. Sultan Singh.

SHRI NIREN GHOSH : Sir, what is it?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : You want to speak ?

SHRI NIREN GHOSH : Yes, I am speaking

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : I thought you were not in the mood.

SHRI NIREN GHOSH : I was speaking and you interrupted me. So, I kept quiet.

श्री एस० डी० मिश्र : दिक्कत यह है कि वे खड़े रहते हैं और मालूम होता है कि बैठे हैं ।

श्री नेकी राम (हरियाणा) : मुझे कुछ कहना नहीं, लेकिन थोडी गलती यह हुई कि वह खड़े हैं और आप ने सोचा कि वे बैठ गये ।

SHRI NIREN GHOSH : Sir,, I was saying that it is really tragic that under the so-called Constitution we are being compelled or rather forced to take up different State Budgets, Presidential Proclamations and the rule of the Centre in different States. All those proclamations so far have revealed one sordid thing, *i.e.* the Governors are an instrument in the hands of the Centre, the Union Government, to subserve its political ends which have no relation with the welfare of the people of the States concerned.

Take, for example, our Governor. He is still there. I hear he is going to be transferred to some other job and one Mr. Viswanathan from Kerala is going to my State. In our State the Governor used to tell us, I am an instrument of the Centre ; so what the Prime Minister tells me, I will do. That is how he used to tell us. So, Shri K. C. Pant, the honourable Minister, was telling us that he had no opinion on the step taken by the Governor, Dr. Pavate. But perhaps in an unguarded moment he referred to some honourable Member's suggestion that the Governor should have explored the possibility of the formation of an alternative Government so that he was not criticised by anybody. So in effect he said that the Governor's action is open to criticism indirectly, obliquely. None 'the' less it is true perhaps in this case the step taken by the Governor has not served the purpose of the ruling Congress, perhaps. That is why in an indirect way Shri K. C. Pant did comment that the step should not have been taken in this matter. Now, what is a Governor ? What is the scope, what are the powers and functions of a State Government ? Even whatever there was in the Constitution over the past two decades, the Centre has encroached upon the rights and privileges and functions of the different States of India. That has been the position. And in this matter, the Governors, the posts of Governors, have served as convenient tools, all along, in the hands of the ruling Congress. So there are double standards on the part of the Union Government. Why, not double standards, any number of standards they can set up to suit

their convenience, when they find any Government which is in opposition to them functioning in any State. Whether the Akali Government was an efficient Government or there i as corruption there—corruption is there eery where ; in all Congress Governments here is co.r'uption ; in the DMK Governnent which is a holy ally of Shrimati Indira Gandhi now, charges of corruption have been levelled againsl. .

SHRI G. A. APPAN (Tamil Nadu) : On a point of order, Sir. How can our friend say anything against the DMK Government ? He can speak only about the Punjab Go\ernment, he can only speak on the subject \.hich the House is discussing now. How can he talk about the DMK Government ? It is not fair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : You are right. Mr. Appan. Please sit down.

SHRI G. A APPAN : Why should he drag the name of the DMK Government into the picti re ? It is very unkind. Please give him instructions not to do so hereafter.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : Please do not refer to other governments.

SHRI NIRI N GHOSH : Now when they are allies of the ruling Congress, they choose. . .

SHRI G. A. APPAN : What is your ruling, Sir ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : I have requested him not to refer to other governments.

SHRI G. A. APPAN : Thank you very much.

SHRI NIREN GHOSH : But that was not the case what Shri Annadurai was alive. The character of DMK was a bit different when Shri Annadurai was alive. Shri Appan should know that was then a big difference.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : Let us come to Punjab Budget.

SHRI NIREN GHOSH : Yes, Punjab Budget. Under Shri Annadurai's leadership, it was different. Now they are in alliance with the Tilling Congress. They could come to an electoral understanding under which this great Congress Party consented not to contest any Assembly seats. Such is the character of their abiding influence. That is why DMK is now protesting too much.

The question is whether the time has not come for this system and these Constitutional practices to be changed. That is the simple question that is posed c ich time when the State budget or Presidential proclamation comes up here for the approval of Parliament. Look at these numerous instances of sordid, under-hand, b ick-stage dealings and conspiracies in order to use the Governors for Party ends and not the ends of the State. It has been discussed time and again. Has not the time come when this archaic post of Governor should be abolished altogether ? There should not be any Presidential proclamation and Presidential rule in any of the States of India.

Sir, 1 do not know. You are a great lawyer and you can enlighten me. In that country which is your source of inspiration in many matters, namely, the United States of America, there is federal system in their own way. The federal government rules the States of USA. As far as I remember, I have not come across any instance when there was any President Nixon's proclamation over a State of the United States of America. But here there are proclamations galore, as if the peoples of the States are like chattle to be bartered or handled. That is how Delhi is treating the peoples of the States of India. *(Time bell rings).* Sir, I have just begun. Therefore, I feel that this system of Presidential proclamation and Presidential rule should be abolished. If there is any crisis, the State Assembly should be called to decide it.

The Assembly is, after all, a body of the elected representatives of the people of the State concerned. If no government can be formed, the Assembly will decide, make some *ad hoc* arrangement and order fresh election. This is how it happens in every State and this should apply to all the States of India. Otherwise, the so-called State Legislatures and the State Governments really have no powers to bring about any I serious changes for the welfare of the people I of their States. So, Sir, that is the one

[Shri Niren Ghosh]

point that I would like to say. Then, Sir, I would like to state that this Constitution should be fully amended, the post of Governor should be abolished and the States should govern themselves through their Legislatures and if a government cannot be formed or if a government cannot function, some *ad hoc* arrangement should be made by the Assembly concerned or a fresh election ordered as it happens in every democratic country of the world.

Now, Sir, it is being said that the Punjab issue took on a communal colour, communal politics. I do not know whether it is reflected in the Budget.

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : Mr. Niren Ghosh, you will appriciate my request.

SHRI S. D. MISRA : Why not, Sir ? These things are to be mentioned in a speech like this.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : No, Mr. Misra...

SHRI S. D. MISRA : These things can be in a general form or in a particular form.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : Mr. Misra, I need not be advised by you.

SHRI S. D. MISRA : Sometimes we are guided by you and sometimes we also guide, Sir. It is mutual. We are advised by you and we also advise. Sometimes you also pull us up, Sir.

(Interruptions)

SHRI NIREN GHOSH : Of course, I disagree with Shri Man Singh Varma when he says that the DMK is a communal party. It is not a communal party. On that point I seriously disagree with him. The DMK is not a communal party. He said that it is a communal party, I say it is not a communal party. What is a communal party ? A Hindu Party, a Muslim Party, a Christian Party, a Buddhist Party—these are communal parties. But the DMK is not a communal party in that sense. I^1 is a party of Tamil Nadu trying to speak for the Tamil people though it is not speaking for the Tamil people now.

SHRI S. D. MISRA : It is speaking for the Centre.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE : Sir, are we discussing the DMK now ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : Mr. Yajee, you are not in your seat.

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON (Kerala): Sir, Mr, Yajee should not be there.

(Interruptions)

SHRI NIREN GHOSH : Sir, I am being disturbed. So many people are disturbing me. What can I do 7 So, Sir, it is trying to speak for the Tamil people and Tamil Nadu. That is what the DMK is doing. It is not a communal party.

SHRI G. A. APPAN : Sir, in spite of your request or advice he is mentioning it and he would not comply with my request. The time for every word is precious and he is wasting the time of the House and is wasting the time of the poor Reporters.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : Yes, Mr. Niren Ghosh.

SHRI G. A. APPAN : Let him not mention the name of the DMK hereafter. Let him confine himself to the Punjab.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : Mr. Ghosh, please...

SHRI G. A. APPAN ; Anyway he goes on wasting the time of the House.

SHRI NIREN GHOSH : Now, Sir, it ill befits Shri K. C. Pant to raise it. The Muslim League is in holy alliance with them. When the Congress Party...

SHRI MAHAVIR TYAGI : Muslim League is no more communal.

SHRI NIREN GHOSH : When the Congress Party. .

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : We are discussing the Punjab budget ; I have told you a hundred times.. *{Interruptions)*.. Please finish. I request you to finish. Please sit down.

SHRI NIREN GHOSH : Now, Sir, this Party has not spoken in a voice that is the voice of the people of India, on the issue of Bangla Desh. Still Mr. K. C. Pant comes here and raises "he bogey of communalism. Wonderful. That is the morality of the Congress Party...

SHRI MAHAVIR TYAGI : Do not say 'Congress Party'

SHRI NIREN GHOSH : Ruling Congress Party. 1 stand corrected...

SHRI S. D. MISRA: Defector Congress...

{Interruptions)

SHRI NIREN GHOSH : It was not proper for the Congress, the spokesman of the Congress, to raise the bogey of communalism when discussing the Punjab budget That is my point.

SHRI RAJNARAIN : What is communalism ?

SHRI NIREN GHOSH : That I have already explained.

Sir, I do not wish to side with the Akali Party, because our politics differ. *On* certain points we might agree. For instance, when the General Secretary of ihe Akali Dal said that barring certain subjects, all powers should go to the States, I am in complete agreement wito the Akali Party. I am in complete agreement with it. My hon friend, Shri *S.* D. Misra, said that the question of Centre-State relations should be re-defined and it should be re-defined in the direction of giving more powers to the States. On that point I agiec.

Now, along with this Budget or this Proclamation, a declaration should have been made by the Government when the election is going to be held in Punjab, because, suppose—now it is June—you hold the election in February or March next year, this President's Rule means the Congress Rule. And the Congress will manoeuvre in such a way during this period that when elections are held, these will be held under the aegis of the Congress. There is no caretaker government or State machinery to take care of things. So this is a great lacuna we do not like. Wherever any State Government has fallen into a crisis, elections should be held immediately. Why should the people be kept subject to the rule from the Centre rule from Delhi, for a longer period—six months or one year ? Why ? Are the Punjabis, these brave people of the border State, slaves ? Why should they be without their own government for a longer period—for ten months ? Why ?

Then, Sir, about the budget, it should not make any changes in the reactionary direction ; or measures should not be taken during this period in any reverse direction. The *status quo* should be maintained. Or, if any step is taken it can be taken in the progressive direction. But I have no faith in the Congress Government, in the the President's rule, that this budget will provide land to the tiller, that this Budget will come down heavily on the wealthy classes and get more taxes from them. Punjab is a wealthy State. It has big farms there. I know many Generals have taken to agriculture. They are capita-talist farmers ; they are big farmers. Those upper strata of the villages, the rural bour-geoisis who are very rich, they should be taxed. And in a Budpet that does not provide for radical agrarian reforms in Punjab, it does not provide for anything because, after all, Punjab is mainly a rurul State. It is not an industrial State. Of course, in India all States are rural States, Because everywhere industry is ill developed compared to the number of industries in any State. But even then Punjab is totally an agricultural State. Some industries are coming up there but they are small-scale industries by any standard. There, all surplus lands should be taken away from the owners. There should be a limit placed in Punjab on agricultural holdings. Even five acres or even three acies are sufficient for the svell-being of family there because there is the multiple-cropping system there. There are crops ar; grown three times and four times **in a** year. **That being** the posj-

[Shri Niren Ghosh]

tion, lands above the ceiling, say, five acres, should be taken away from the owners and the surplus should be immediately distributed to the landless peasants. This step should be taken, and also the rural indebtedness in Punjab should be written off because in Punjab there are not only the indebted farmers but also the agricultural labourers. Though the wage packet in cash of the agricultural labourers in Punjab is not small but is more than what it is in other States still, in relation to the price level soaring uf> there, their wages have not risen ; actually their real wages have fallen in Punjib, I mean the real wages of the rural poor So, any Budget of Punjab which does not provide for a proportionate rise in the real wages, which does not provide for fair wages to the rural poor in Punjab, that Budget cannot be supported. A Budget that does not take away all the surplus lands beyond the ceiling of, say, five acres based on the requirements *of* an average family, and distribute it immediately to the landless peasants and the agricultural labourers in this order, is no Budget of Punjab. A Budget which does not provide for the soluion of the power crisis in Punjab is no Budget at all.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARBAR ALI KHAN) : Mr. Niren Ghosh, you kindly finish noiv. You have taken more time than required.

SHRI NIREN GHOSH : Hew much time I have taken, Sir ?

SHRI RAJNARAIN : You have taken nothing.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : Please conclude now.

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON : When there is President's rule in Punjab now, the affairs of Punjab should be fully discussed and this House is the custodian of the democratic rights of the people of Punjab.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : He does not need your support, Mr. Menon.

SHRI NIREN GHOSH : So, Punjab is an important State. Why should at all a power famine occur there ? What does this Budget say about this power famine ? Why has the le el of water gone down ? Why is the Bhakra reservoir not functioning ? What are the steps that are proposed to be taken—that should be brought to our notice ? Is this the Budget prepared by pedestrians or the Akalis.

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa) : Where are the Congress Members from Punjab. There seems to be no Member in the ruling Party who comes from Punjab. Have they no interest in Punjab ? Have they absolutely no interest in the well-being of Punjab ?

SHRI SULTAN SINGH (.Haryana) : We are here . . .

(Interruptions)

SHRI NIREN GHOSH : What can I do if other Members are interrupting ?

SHRI S. D. MISRA : At least you should yield to the lady.

SHRIMATI YASHODA REDDY (Andhra Pradesh) : 1 was answering Mr. Lokanath Misra that the Punjab Members are sure that you will look after their interests, and that is why they are not here.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : Now you have taken a lot of time. Now please sit down. I request you to sit down.

SHRI NIREN GHOSH : Sir, a bit more. I was on the point of the Punjab Budget. It has appeared in the press that if you talk of corruption, then there are olficer circles all along the chain and I suppose, such chains are also operating in the Central Government officers and staff. Such things do happen.

The Budget should make some provision for routing out corruption. The charges and counter-charges of corruption should come out. If there is corruption, let the dirty linen be washed in the Public, so that the public comes to know about parties,

institutions, officers—whoever are concerned — in their proper right Now, Sir, there are Officers in the Fssential Services who ha'e come on loan to the Punjab Government. That system should end Sir, all officers in a Sta"e— in Punjab a'so— should fully uider the c mt-ol of the State Government. Either they should remain under the control of the State Government or thos; offiocr-^ s ould be withdrawn from all States and from Punjab also. So, the Budget should orovide that no Central Government offkers can s'ay there. They shou'd be under he c^n'rol and discip'ine of the State Government concerned. That should be- the practice. As regards food grain* in Punjab Sir, . . .

SHRI OM MEHTA : How long are you going to take ? You have already taken hail-un-hour.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): No, no, you are not co-operating *iih me.

SHRI NIREN GHOSH : What will happen to the question of foodgrains ? This is a moot question because, being capitalists, if all those big Birlas sell at t*,e exorbitant prices to Hie peop.e of India, it is a crime. So. what has the Budget to tell about that ? You must te.l us. Prices should be fixed. A fair p.ice giving six per cent of profits and not more than that should be fixed.

The entire surplus should be procured by the State so that others can get. Has the Budget piovided for that and for the industrialisation of Punjab.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRi AKBAR ALI KHAN) : Have you read the Budget ?

SHRI NIREN GHOSH : I want to see all parts of India fully industrialised so that 50% of the people are indusirial workers and only the other 50% should be engaeed in agriculture but what is the percen age in any State, not to speak o[r] Punjab ? So far a'l that the Ruling Congress is responsible and even in corruption, they are leading throughout India and in Deihi also. So th y cannot speak abou it. So why should we dis.-uss this Budget ? The Parliament should not discuss this. Birring certain things, the States shmld discus? them. The Constitution should be amendeJ al ve ctnnot go into the de'ai's f the Punj ib Budget and the big papers yo i have given us. Then give us some S-creta ies to go through the Budget so that we can go into the detai's. That you can do. Whv should we int-rfere in the affairs of Punjab or any State and why should these things come b;f ire us agiin and agiin? This is against de nocracy, gainst all standards. It is o->ly for the privilege o'" the nunopalists and their P irty, the Cong'd'-s, and the States have been ench died by the Ru'ng Congress with the Centre This sy tern should go and the Punjabis, a brave peoble, wi'l themselves root out corruption and enure a democritic sytem. So this Budget should he thoroughly recast and the bi ts s'lou'd be in favour of the people. That being so, I think this Budget should be recast and redrafted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : The Minister.

श्री राजनारायण : हमको भी तो बजट पर बोलना है ।

TH^ VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): I have no objection if you want to go on like that. I am following wiot the Business Advisory Committee has laid down.

श्री राजनारायण : अरे, आप एक घन्टा अलाट कर दीजिए —इससे क्या होता है ?

THE VICE-CHAIRMAN 'SHRI AKBAR All KHAN): The other thing is we are taking the Appropriation Bill also. So if we finish 'he Budget and then take up the Aopropriation Bill, then I will give you, Mr. Sultan Singh, Mr. Bhupesh Gupta and Mr. Artpan time. If you want to speak on this, I have no objection.

Sim BHUPESH GUPTA ; It was so kind of yon . . .

SHRI OM MEHTA : Two hours were jointly allotted for the Budget and the Aporopriation We hive a ready taken an houi and a quarter, for Budget.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : I think we have exceeded the time.

We have to follow certain principles. The

श्री राजनारायण : श्रीमन्, अगर गवर्नमेंट यह कर दे कि एक घन्टा में खत्म कर दो, तो वह एक घन्टे में वो खत्म हो सकता नहीं।

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : राजनारायण जी, आप मेरी रिक्वेस्ट तो सुनिए।

श्री राजनारायण : आपको बहुत सुन लिया।

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : मैं यह कह रहा हूं—we have to follow certain principles. . .

Business Advisory Committee is meant for that and we must follow the Business Advisory Committee's decision.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI

श्री राजनारायण : मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चीज को एडवाइजरी कमेटी में पुनः भेज दिया जाय। पजाब का बजट एक या दो घन्टे में पास नहीं हो सकता है। चाहे एक राज्य का हो या चाहे सारे देश का हो, इस तरह से बजट पास नहीं हो सकता है।

AKBAR ALI KHAN) : That is not in my power.

[MR. DEPUTY-CHAIRMAN in the Chair]

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE/**वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री** (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI) : Mr. Deputy Chairman, I was already holding the floor of the House when I was called by the hon. Vice-Chairman to speak. I only sat down in deference to the Vice-Chairman's request, But I still hold the floor.

SHRI BHUPESH GUPTA ; We have no quarrel with the hon. Minister at all. 'We have no controversy with her in so far •as she and we are concerned over the subject-matter under discussion.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Then, with whom have you to quarrel at present ? I am told she was called. I cannot go back on that. She has been called.

श्री राजनारायण : जरा आप हमारी बात सुन लें। यहां पर धांधली के साथ काम नहीं चलेगा। (*Interruptions*) यहां पर गलत कहा जा रहा है। पहले चेयर ने हमको बोलने के लिए कहा। हमने कहा हम भी बोलेंगे और श्री भूपेश गुप्त जी भी बोलेंगे। मगर जैसे ही नीरेन घोष बोलने से बैठे तो मिनिस्टर साहब को बुला लिया गया। (*Interruptions*)। हम सुशीला जी से कहना चाहते हैं कि हमारी उनके साथ कोई लड़ाई नहीं है।

(*Interruptions*)

श्री उपसभापति : मैं तो यह समझता था कि यहां पर दूसरा काम शुरू हो गया होगा, लेकिन अभी तो बजट पर ही चर्चा चल रही है। (*Interruptions*) एप्रोप्रिएशन बिल जो है वह भी बहुत इम्पोर्टेन्ट है।

AN HON. MEMBER : The Budget is more important.

SHRI BHUPESH GUPTA : Mr. Deputy Chairman, you are developing the mentality of an old uncle. You want to save the situation by shjwin? a little toy here and there. Why are you assuming tho role of an old uncle ? You are here. The Bill is under discussion. Let the discussion go on.

MR. DEPUTY CHAIRM\N : We had agreed in the Business Advisory Committee meeting that two hours would be allotted. We have taken about l£ hours now.

SHRI BHUPESH GUPTA : We are prepared provided yon do not bring the Maintenance of Internal Security Bill. You withdraw it and everything will be all right.

(Interruptions)

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Order, order please.

SHRI BHUPESH GUPTA : It is a political decision. We assume that it is an extraordinary situation and you are hurrying througl ,

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I am not hurrying through. I am told that the Vice-Chairman his already called the hon. Minister. I cannot go back on that. That is my difficulty.

SHRI BHUPESH GUPTA : All your life you have gone back. You are sitting there beeause you have gone back.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I will eall the Minister to reply. Please listen. We will again consider the Punjab Appropriation Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Unless you are called by the Chair, you cannot speak and you cannot thrust your speech. He did not call you.

श्री राजनारायण : मैं चेयर की इज्जत के खिलाफ कोई बात कहना नहीं चाहता हूँ। सारी संसदीय प्रथा को छोड़ दिया गया है। जब हमने कहा है कि हम बोलेंगे, तो उन्होंने मन्त्री जी को बुला लिया।

श्री उपसभापति : अब आप बैठ जाइये। मैं यह कह रहा हूं कि वाइस-चेयरमैन ने मिनिस्टर को रिप्लाई देने के लिए कहा. . .

श्री राजनारायण : क्यों कहा ? (*Interruption*) अकबर अली खान साहब का नाम काटिये। यह कोई तरीका है कि बुलाते हैं अरोड़ा को और खड़ा हो जाते हैं गैर-अरोड़ा।

श्री उपसभापति : राजनारायण जी, इसके बाद मैं ऐप्रोप्रिएशन बिल आ रहा है। जो आप बजट पर बोल सकते हैं वही आप ऐप्रोप्रिएशन बिल पर बोल सकते हैं। और कोई बात कहने के लिए राजनारायण जी को कोई सब्जेक्ट चाहिये नहीं, वे कोई भी बात किसी भी सब्जेक्ट पर कह सकते हैं। जो बजट पर वे कहें वही वे एप्रोप्रिएशन बिल पर कह सकते हैं। इसी लिये मैं कह देना चाहता हूं कि वाइस-चेयरमैन ने जो उनको बुलाया जवाब देने के लिये तो उनको जवाब देने दीजिये। एप्रोप्रिएशन बिल आ रहा है और जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, वे उस पर बोल लेंगे।

श्री राजनारायण : मैं आपको बताऊं कि नीरेन घोष जी नहीं बोल रहे थे। हम यहां पर आये तो हमने नीरेन घोष जी से कहा कि आप पहले बोल लीजिये, हम बाद में बोलेंगे। ये सारी बातें वाइस-चेयरमैन साहब को मालूम हैं।

(*Interruption by Shri Sheel Bhadra Yajee*

शीलभद्र याजी जी, मैं आपसे विनती करता हूं।

श्री शीलभद्र याजी : श्री नीरेन घोष और आप में समझौता है।

(*Interruption*)

श्री उपसभापति : राजनारायण जी, हम आपको बोलने देंगे एप्रोप्रिएशन बिल पर।

(*Interruption*)

श्री एस० डी० मिश्र : श्रीमन्, एक बात मैं कहना चाहता हूं। आप यह देखें कि श्री भूपेश गुप्त और श्री राजनारायण इस बिल पर शुरू से बोलना चाहते हैं। (*Interruption*) इस टेक्नीक्विलटी पर कि चेयर ने मिनिस्टर को बुला लिया आप यह नहीं कह सकते. . .

(*Interruption*)

श्री उपसभापति : चेयर को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो निर्णय लेती है, उसके मुताबिक काम किया जाय।

श्री राजनारायण : इस विषय पर किसी पार्टी के प्रतिनिधि को बोलने से चेयर रोक नहीं सकती है। बजट पर हर पार्टी का अपना-अपना नुक्ता नजर होता है। (*Interruption*) अभी इस पर लोकनाथ मिश्र जी बोलेंगे, अभी इस पर भूपेश गुप्त जी बोलेंगे, अभी इस पर हम बोलेंगे।

श्री शीलभद्र याजी : कौन से रूल में है।

श्री राजनारायण : यह संसदीय प्रथा के रूल में है।

SHRI ICK^NATH MI^RA : Sir. I have a sutmis[c]irn to make. 1 agree that the Business Advisory Committee has allotted t«o hours for both, and it was for the Chair to lo< k through the names of different parties and to a/lot lime accordingly. If the CI air could not control son e pariicular Member, other Members he'onging to other parties should not be blamed for that or they should not be taken to task for that. The point is that the Chair either should be in a position to control time and control Members accordingly or else there should not be any attempt from the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Is it possible for the Clair to control Members without the co-operation of the House.

SHRI LOK.ANATH MISRA : I qui'e agree that co-opera'ion of the House is necessary, but to deprive other Members because some other Members has taken mote time . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I am not depriving. What I am suggesting is instead of speakirg en tie Budget jou can speak on the Approprialicn hill and ex-pie«s tl e stme view or ever, an a erra'.e \iew. In view of tie opinion expensed b) Shri lokanath Misra 1 am prepaiea to say this tl ing if the House igrccs. We stolid allow some other Members to express their views on the Budget 1 lave no chjic itn. provided the Appropriation 1 ill will te passid witl.c ut further discission. 1 am picrared to do that.

SHRI GANESHI LAL CHAUDHARY (Uttar Pradesh) : 1 want to speak on the Approprialicn Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : We have already taken more *time.* The sibject-maiter is tie same. They can speak on the Appropriation hill. Otherwise il tl.ey want to speak on ihe Budget, then no further discussion on the Appropriation Bill.

We pass it, I mean, we put it before the Hcuse without further discussion. Let the House agree on this proposal.

SHRI S. D. MISRA : One does not know what the Minister is going to say on the Approptia'i'wi Bill, and then we cannot throw off the responsibility of saving anything. We carnot anticipate what is the argument of the Minister.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : After having hea d the views of the hon. Members, she will reply. Thit is what she has said in the morning.

श्री गणेशी लाल चौधरी : श्रीमन्, बजट पर बोलने का दायरा दूसरा होता है और एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने का दायरा दूसरा होता है। क्या जरूरी है कि बजट पर जो हम बोलेंगे वही एप्रोप्रिएशन बिल पर भी बोलेंगे ?

MR. DEPUTY CHMRMAN: You cannot have it both ways. The Business Advisory Committee has decided it.

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON : Sir, may I draw your atteniion to the fact that normally a Slate Government's Budget is discussed for \\ months to two months in the State Assembly and here, we should like to knew. . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN : No, no. it is a question of ihe Rajya Sabha here, v\e du not know about the Assemblies.

bHRI K. P. SUBRAMANIA MENON: In order to he fair 10 ihe pei pie of Punjab, in older lo see i at their problems are properly discussed in this Hou e, it is i.ot correct that we to al ead with this discussion in such a Lurried manner, lo finish it in i| hours W 1 en the\ lakf two months in the S.aie Assembly, jou shuu.d noi finish it here in two lours. This is teiy ni.l'air to ihe people of I-unjab, very unfair lo this Parliament and very unlair to ihe idea of. . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The Business Advisory Con miliee has already e'ccideel the time. Il Las c'ecie'ed tl at two hours should fce allotted for this discussion.

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON: The Business Advisory Committee was absolutely vvroag in that. It had no idea about this.

SHRI OM MEHTA : When the recommendations of he Business Advisory Committee were announced, any Member could have raised this at that time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : When the Business Committee's decision was announced in the House any Member coi'ld have objected that Punjab business required two days and not two hours. Nobody objected then.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL (Gujarat) : We are in a democracy. This House can change the decision it has taken. Why not ?

SHRI NIREN GHOSH : Why not ? Is it obligatory or mandatory ? It is a guideline or a recommendation to the House that it should b<- conducted in this manner. The recommend.uion we tan modily.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं एक जानकारी करना चाहता हूं कि क्या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जब बैठी थी तो उस समय पंजाब का बजट कैसे आयेगा, किन-किन मदों पर कितना खर्च होगा, टोटल बजट का एमाउन्ट क्या होगा. यह सब बातें वहां सामने थीं या उसने अधकार में अंधा फैसला लिया है ?

MR. DEPUTY CHAIRMAN : We had a meeting on the last Thursday.

श्री राजनारायण : कितने मदें हैं, किस मद पर कितना खर्च है, कोई इसकी चिन्ता नहीं और फैसला आप ले लेते हैं।

श्री उपसभापति : मुझे पता नहीं, मेमोरी से बोल रहा हूं. . .

श्री राजनारायण : जानकारी कर लीजिए।

श्री उपसभापति : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होने के पहले बजट टेबिल पर रखा गया था, ऐसा मैं समझता हूं।

श्री राजनारायण : आपकी सूचना गलत है।

श्री उपसभापति : मैं एक सुझाव दे रहा हूं कि अभी वाइस-चेयरमैन ने मिनिस्टर को बुलाया है. . .

श्री राजनारायण : अगर आप चाहते हैं कि . . .

श्री उपसभापति : एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए। अब मिनिस्टर जवाब देंगे। उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल पर आप लोगों को जितना बोलना हो बोल लीजियेगा।

श्री राजनारायण : या तो आप रूलिंग कर दीजिए कि वाइस-चेयरमैन या चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन जो भी चेयर पर हो वह अगर किसी को बुला लें और उसके बाद वह खड़ा न हो और दूसरा कोई आब्जेक्शन करे तो वह नहीं बुलाया जायेगा। भविष्य के लिए कोई ऐसी रूलिंग हो जाय।

श्री उपसभापति : में आपकी बात समझा नहीं।

श्री राजनारायण : यानी वाइस-चेयरमैन साहब ने बुला लिया और मन्त्री जी बैठी रहीं और मैं खड़ा हो गया और मै मानता हूं कि अभी मैं बोलने वाला हूं, भूपेश गुप्त जी बोलने वाले हैं और यह बहस चल रही है तो आप एक ऐसी बात कह रहे हैं जो अनहोनी है। अगर चेयरमैन किसी मन्त्री को बुलाते हैं तो सदन के सदस्यों को अधिकार है कि कहें कि अभी मन्त्री जी को तकलीफ न दीजिये, अभी हम लोगों की बात सुन लीजिये। मैंने यही बात कही। मन्त्री जी तब खड़ी भी नहीं हुई थीं। बाद में मन्त्री जी को एक चिट आई कि यह

[श्री राजनारायण]

कह दें कि मैं इस हाउस के पजेशन में हूं। उस समय श्रीमती जी हाउस के पजेशन में नहीं थीं। वह खड़ी नहीं हुई थीं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : खड़े होने से क्या होता है।

श्री राजनारायण : अगर बैठना और खड़े होने में कोई फर्क ही नहीं है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You do not know that. राजनारायण जी, मैं कहता हूं कि आपको एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने का मौका दूंगा, तब दोनों बातें कह दें।

श्री राजनारायण : अन्याय के सामने झुकते-झुकते अन्याय को सहने लगते हैं। आप कृपा करके बता दीजिये कि आपके लिये एप्रोप्रिएशन बिल और बजट में कोई फर्क नहीं है। आप ऐसी बात श्रीमन्, कह रहे हैं . . .

श्री उपसभापति : मेरे लिये तो फर्क है। राजनारायण जी, जरा सुनिये ...

श्रीराजनारायण : . . . यह संसदीय प्रथा में अनहोनी है।

श्री उपसभापति : . . . मेरे लिये थोड़ा सा फर्क है ज्यादा नहीं है, लेकिन आपके लिये तो कोई फर्क नहीं हो सकता है ; क्योंकि आपके लिये तो सभी सब्जेक्ट एक सा है, एक तरह का है।

श्री राजनारायण : हमारे लिये फर्क है या नहीं है, वह बाद में देखा जायगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : As a compromise I am prepared to say this much. . .

श्री राजनारायण : काम्प्रोमाइज क्या है ? क्या हमारा कोई पारिवारिक झगड़ा है। हमारा कोई पारिवारिक झगड़ा नहीं है, देश का सवाल है।

श्री उपसभापति : किसी दूसरे सदस्यों का भी कोई पारिवारिक झगड़ा नहीं है, किसी का पारिवारिक झगड़ा नहीं है और जितनी आपको संसदीय परम्परा के लिये सहानुभूति है मैं समझता हूं कि उससे कम कोई सदस्य में नहीं हो सकती है। आपसे ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं। आपके बराबर सब में ही संसदीय परम्परा के लिये सहानुभूति है।

श्री राजनारायण : किसी में हो या नहीं हो, आप में नहीं है।

श्री उपसभापति : आप ठेकेदारी नहीं ले सकते हैं संसदीय परम्परा की।

श्री राजनारायण : मैं निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं करता।

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA (West Bengal) : On a point of order. . .

श्री उपसभापति : एप्रोप्रिएशन बिल पर सब बातचीत कर लेना।

श्री शीलभद्र याजी : गो आउट।

श्री राजनारायण : अब इस समय हम गो आउट नहीं करेंगे, हम यहां बैठेंगे। यह तीन दिन गो आउट नहीं होगा। श्रीमन्, आप इसको गो आउट कराइये।

श्री एस० डी० मिश्र : श्रीमन्, याजी जी को जरूर गो आउट कराइये, जो इस तरह बोलते हैं।

श्री शीलभद्र याजी : आप बीच में क्यों बोलने लगे, दालभात में मूसलचन्द !

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Order, please. Let us listen to Mr. Sen Gupta.

SHRI DWFJENDRALAL SEN GUPTA: Mr. Deputy Chairman, Sir, two points are involved here One is that the Vice-Chairman has asked the Deputy Minister to make her speech. The other is you are also concerned with the time that will be consumed. . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I am DOI so much concerned with time as with the ruling given by the Vice-Chairman. He has called the Deputy Minister.

श्री राजनारायण : यह रूलिंग है कोई।

SHRI S. D. MrSRA : If you see the proceedings of the House you will find that the Minister had to sit down, even after he was called, and hon'ble Members were allowrd to speak. This has happened in the Question Hour, in the Debate, dozens of time. . .

SHRI DWDENDRALAL SEN GUPTA: I am on my legs, Mr. Deputy Chairman. Sir, is it anyw lere in the rules that if the Vire-Chairman or the beputy Chairman or the Chairman asks a:iy Member to make a speech, that decision cannot be revised or revoked ? So there is no such rule. You can, as Deputy Chaiiman, revise the order of the Vice-Chairman and ask Mr. Rajnarain and Mr. Bhupesh Gupta, after him, to speak.

SHRIMATI YASHODA REDDY : There is no such rule. But the point is the hon'ble Minister, as per what has happened, is already in possession of the House, . . *(Interruption)* . . . You listen completely. She was in po session of the House. Other Members can be called only after she finishe-, her speech or they can be called to speak only if she yields.

SHRI RAJNARAIN : She was not in possession of the House. She was in possession of her seat. वह सदन के पजेशन में नहीं थीं अपनी सीट के पजेशन में थीं।

SHRI LOKANATH MISRA : For the information of Mrs. Yashoda Reddy, anybody who is in the possession of the House can also be dispossessed by the Chairman or the Deputy Chairman if there is a revi-si on by the Chairman or the Deputy Chair-tmn of what had been done by the Vice-Chairman.

SHRIMATI YASHODA REDDY : You are right. I am not denying that. But here the Vice-Chairman is not there and the Deputy Chairman is saying that he would like to respect the Viee-Chairman's procedure of calling the Minister.

श्री राजनारायण : श्रीवर्, मैं श्रीमती यशोदा रेड्डी को आपके द्वारा एक सत्य बताना चाहता हूं—इस सदन में असत्य नहीं बोलना चाहिए। यह सही है कि वाइस-चेयरमैन श्री अकबर अली खान साहब ने कहा कि अब मंत्री जवाब देंगे और मन्त्री उठ ही रही है, सीट की पजेशन में है, सदन की पजेशन में नहीं हैं कि मैं खड़ा हो गया। मैंने चेयर से कहा देखिए हम बोलने वाले हैं, भूपेश गुप्त बोलने वाले हैं, मिश्र जी बोलने वाले हैं, हर पार्टी को समय दीजिए। यह बहस ही चल रही है और मन्त्री जी बैठी हुई हैं और जब हम आब्जेक्शन किए और बोलना चाहे तो बीच में खड़ी हो गईं और अब कहती हैं सदन की पजेशन में हूं। सदन की पजेशन में और सीट की पजेशन में दोनों में बड़ा फर्क होता है। वह सदन की पजेशन में नहीं थीं, इसलिए आप कृपा करके हमको बोलने दें. . .

श्री डाह्याभाई व० पटेल : बोलिए। आपको कौन रोक सकता है ?

श्री उपसभापति : नहीं, नहीं, राजनारायण जी। आप एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलिएगा।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, हम आध घंटे में तो हम बोल चुके होते।

श्री नवल किशोर (उत्तर प्रदेश) : टाइम कम लेंगे तो बोलने दीजिए इन्हें।

श्री उपसभापति : उनको-एक घंटा चाहिए।

श्री सुलतान सिंह : वाइस-चेयरमैन साहब ने तो मेरा नाम भी पुकार लिया था।

SHRI BHUPESH GUPTA. : We would like to hear as mtny Congress Members as possib'e. I do not mind even if one Member speaks twice on this matter.

श्री राजनारायण : तो उनको बुलवाएं । वह बोलें तो ठीक है । मैं उनके खातिर तुरन्त बठ जाऊंगा ।

श्री नवल किशोर : आपने क्या कहा ?

श्री ओम् मेहता : मैंने कहा, हमारी पार्टी के नही बोलेंगे ।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, जो हमारे रइसे हरियाणा हैं, उनको बुलवाइए पहले ।

श्री सुलतान सिंह : राजनारायण जी बोलेंगे तो मैं जरूर बोलूंगा ।

श्री उपसभापति : मैं इस पर काम्प्रोमाइज करूं क्या ?

श्री एस० डी० मिश्र : श्रीमन्, काम्प्रोमाइज यह होगा कि राजनारायण जी से हम लोग भी निवेदन कर दें और आप भी कि 20 मिनट में अपना भाषण खत्म कर दें बजाए इसके कि इस तरह से चलता रहे ।

SHRI OM MEHTA : My party has conceded its right to speak.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Misra. you are Deputy Leader of the Opposition. What I say is, we allotted two hours for this a>"d we have already taken 1 hour and 45 minutes. We can extend it by one hour more. What I suggest is, let us conclude the debate on the Budget, and on the Appropriation Bill let us not take much time.

(Interruptions)

SHRI S. D. MTSRA : But please do not shut out our speeches.

MR DEP'TY CHAIRMAN: All right, how much time do you want to allow for the Appropriation Bill ?

SHRI S. D. MISRA : No exact time, but not many sneeches. We agree that there should not be many speeches on the Appropriation Bill.

MR. DEPUTY CHMRMAN : No. no, how mueh time do you want to allow for the Appropriation Bill ?

SHRI S. D. MISRA : I would say, not more than one hour for the Appropriation Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Ts it the decision of the House that only one hour will be allotted to this Bill ?

HON. MEMBERS : Yes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN; All right, we will proceed with the Budget. Mr. Rajnarair.

SHRIMAT! SUSHILA ROHATGI : On a point of order, Sir. There is to put the record straight Let me plaee the facts, I was called upon by the hon, Vice-Chairman and I did stand up, whatever the other Members may say. But if you have decided to continue the debate. I will stand by it. But things must be put straight.

श्री सुलतान सिंह : श्रीमन्, मेरा नाम भी पुकारा गया था ।

श्री उपसभापति : जैसा कि मन्त्री महोदय ने थोड़ा सा आब्जेक्शन ले लिया है, वह भी अपनी जगह पर है. . .

श्रीमती सुशीला रोहतगी : नहीं आब्जेक्शन कुछ नहीं है ।

श्री राजनारायण : क्या आब्जेक्शन है मन्त्री महोदया का ?

MR. DEPUTY CHAIRMAN : She was called.

SHRI BHUPFSH GUPTA : She was not called, you forget, Sir ; she was miscalled.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: She was c-Uled, she I tood up avid she was in possession of the 1 louse.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Bhupesh Gupta, now the only question is this. If the Vice-Chairman called the Deputy Minister to reply to the debate and if we aie not allowing her to reply to the debate, . . .

SHRI BHUPESH GUPTA : No, no. We are not coming in her way.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : ... my question is how In g we have to ask her to wait. She is in possession of the Hcuse but we are asking her to sit down and we are saying, let other Members also speak . . .

SHRI BHUPESH GUPTA : Let me tell you how long you can ask her to wait First may we know, Sir, the limit of our patience because unless we have some idea of our patience, how can we give an opinion how long she has to wait 7

SHRI MAHAVIR TYAGI : If the Government announces that it will not press the Preventive Detention Bill, then the whole topic is ever, 1 am sure.

SHRI BHUPESH GUPTA : ST, you are in the Chair. I rise on a point of ord.r You must see that the Government does not handle the business of the House with a view *to* passing a certain measure which is uppermost in its mind and which is resented by th; entire Opposition All this has'e on the part of the Government here is only to sea that the Preventive Detention law is passed ; otherwise, there is justifi-action for this haste Since we are opposed to the preventive law, which they would perhaps pass, we are not in a mood today to accommodate the Government And as far as patience is concerned, I think our lady Minister has infinite patience . . .

SHRIMAT) SUSHILA ROHATGI : It has already been tested.

SHRI BHUPESH GUPTA : . . . **and** she will vait here. I am sure this is one of her great qualifies that she has ample patience.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : What 1 suggest is this. We have taken nearly two aours for the Budget. Instead of one hour we have taken two hours. My suggestion is about forty-five minutes more will be enough for discussion in the House and about twenty minutes for the honourable Minister to repiy to the debate.

SHRI BHUPESH GUPTA : I do not know, you are now distributing the social justice which we hear in the Budget speeches. It is so ill justice that twe.ity minutes are allowed to one peison and fort>-five mi.utes to all of us put to-ge.her ?

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Otherwise, how can she reply to all the points of honourable Members ? If she does not reply to your points, you will say she has not answered your points. That is why she requires a little more time for replying to the debate.

SHRI BHUPESH GUPTA : Her reply will be excellent, I know. We do not quarrel on that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : But if you say she need not reply to all the points, then she will finish within five minutes.

SHRI BHUPESH GUPTA : Even if she speaks for six hours we will have no objection.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : It is all tight. Now let us take forty minutes for discussion. Mr. Rajnarain to speak now.

श्री सुलतान सिंह : आपने हमको बोलने के लिए कहा था ।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं यह कहता हूं कि चेयर ने हमको बुलाया था बोलने के लिये कहा था ।

श्री उपसभापति : किसको बुलाया था, उनको बुलाया था या तुम को बुलाया था ।

(*Interruptions*)

श्री राजनारायण : जब आपने उनको बोलने के लिए कहा है तो उन्हें पहिले बोलने दीजिए और हम बाद में बोल लेंगे। मैं यह भी चाहता हूं कि यहां पर कुर्सी दुरुस्त रहे। यहां संसद में, राज्य सभा में जो विरोधी सदस्य हैं वे बजट पर अपना नुक्ते नजर रहने का हक रखते हैं और उनके हक को आपको कबूल करना होगा।

श्री उपसभापति : आप अपना भाषण आरम्भ करें।

श्री राजनारायण : मिनिस्टर साहब बीच में उठ गईं थी और इसीलिए हम अपने अधिकारों के लिए बीच में खड़े हो गये। फिर बाद में वे खड़े हुये।

श्री शीलभद्र याजी : गलत बात है।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं इस बात को पहले ही निवेदन कर दूं कि यह जो पंजाब के लिए बजट प्रस्तुत है राज्य सभा में यह सामान्य लोकतंत्रीय और संसदीय प्रथा के विरुद्ध है। पंजाब की जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधि अपने क्षेत्रों के बारे में जानकारी रखते हैं और वे अपने क्षेत्रों के बारे में अच्छी तरह से बोल सकते हैं। यहां जो हम संसद के लोग बैठे हुये हैं हमको पंजाब के बारे में विशेष जानकारी नहीं है। इसलिये पंजाब राज्य के बजट को संसद द्वारा पारित करना यह अजनतंत्रीय है।

श्री उपसभापति : इसलिए आप बैठ जाइये।

श्री राजनारायण : इस बात को मैं चाहता हूँ कि आप ज्यादा अच्छी तरह से समझें। संसद सदस्य चाहे कम समझें तब भी काम चल जायेगा। मैं बहुत ही तकलीफ के साथ इस बात को कह रहा हूं कि यहां पर हर समस्या पर हड़केभोंग पैदा कर दिया जाता है। आधा घंटा केवल इसमें लग गया कि कौन पहले बोले, कौन न बोले, कौन बजट पर बोले और कौन एप्रोप्रिएशन बिल पर बोले।

इसलिये मैं चाहूँगा कि सदन के सम्मानित सदस्य जरा बजट के प्रस्तावों को अच्छी तरह से पढ़ें। सम्पूर्ण बजट देखा जाय तो जो शासकीय दल बार-बार यह चिल्लाता रहता है कि समाजवाद, सामाजिक न्याय आर्थिक समानता लाई जायेगी, क्या यह बजट समाजवाद, आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय का है। सारे प्रस्तावों को आप श्रीमन्, देख लेंगे तो इसमें कहीं भी जो 5 अरब से ऊपर का बजट है हरिजन उत्थान के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, हरिजन उत्थान की कहीं चर्चा नहीं है। यहां हरिजनों के बच्चों को स्कालरशिप देने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें एक अजीब व गरीब सी चीज नजर आयेगी। अगर हम ठीक से देखेंगे तो हमें मालूम होगा कि सरकारी सेवकों के लिए उधार की व्यवस्था की गई है और 28 करोड़ . . .

श्री नेकीराम : मैं अपने साथी को बताना चाहता हूं कि इस बजट में हरिजनों के लिये जो रखा गया है, उसको पहले पढ़ कर वे बोलें तो अच्छा रहेगा।

श्री राजनारायण : यह सब हमारे समय में न जोड़ा जाय। मैं यह पुनः कहना चाहता हूं कि राज्य सभा के द्वारा या संसद के द्वारा पारित होने वाला जो पंजाब का बजट है, उसमें प्राइवेट पार्टियों और सरकारी सेवकों का उधार देने के लिए 29 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह अजीब बात है। यह प्राइवेट पार्टियां कौन होंगी, किन को उधार मिलेगा। जो सरकारी लोग होंगे उन्हीं को उधार मिलेगा। सरकारी सेवकों को जो उधार दिया जायेगा उसकी कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है। सरकारी सेवकों के बहाने जो मंत्रियों के चहेते होंगे, उन्हीं को उधार मिलेगा और जो ईमातदार सरकारी सेवक होंगे, वे अपनी जगह पर टायं-टायं फिस रहेंगे।

इसलिए कित ी बेहूदगी से भरा हुआ यह बजट है। मैं चाहता हूं कि आप खुद इसको देखें और सदन के साम्मानित सदस्य भी देखें। बिना पढ़े, बिना बजट के प्रस्तावों का अवलोकन किये हुये अधाधुंध एक भेडियाघसान चलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पास कर दो, पास कर दो। यह क्या हमारे बाप की कमाई है या किसी के बाप की कमाई है। यह जनता का धन है, जनता की निधि है और जनता के धन के साथ इस प्रकार से अन्यायपूर्ण तरीके से बजट को रखना बिलकुल अन्याय है। श्रीमन्, मैं और आगे चल कर आपको बतलाऊंगा, लेकिन अभी कहना यह चाहता हूं कि यहां पर बराबर कोठारी आयोग की चर्चा की जाती है और कोठारी आयोग के साथ दूसरे आयोग हैं, राधाकृष्णन आयोग, नरेन्द्र देव आयोग, शिक्षा के सम्बन्ध में जितने आयोग बने हैं, सभी ने इस बात को कहा है कि राज्य के बजट का 20 फीसदी और केन्द्र के बजट का 10 फीसदी शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। 5 अरब रुपये का यह बजट है और शिक्षा के लिये कुल 32 करोड़ रखा गया है। अगर कोठारा आयोग की सिफारिशों को देखा जाय, राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशों को देखा जाय, आचार्य नरेन्द्र देव की सिफारिशों को देखा जाय तो उन सिफारिशों के मुताबिक एक अरब रुपया, सौ करोड़ रुपया शिक्षा के लिए रखा जाना चाहिए था। यह सरकार शिक्षा के लिए कितनी उदास है, किस ढंग से यह शिक्षा नहीं देना चाहती और किस ढंग से आगे लोग शिक्षित होकर समाज में अपनी भूमिका अदा करें यह सरकार नहीं चाहती, इसको देखा जाना चाहिये और इसलिये यह सरकार अनावश्यक प्रशासन की मदों में ज्यादा रकम खर्च के लिए रखती है और जो सामाजिक सेवायें हैं, उनके लिए सरकार कम रकम रखती है। मैंने जब बजट के प्रस्तावों को देखा तो मुझे हैरत हुई कि कारण क्या है कि सौ करोड़ रुपये जहां शिक्षा पर खर्च होना चाहिये, वहां केवल 32 करोड़ रुपया ही रखा गया है। हमारी श्रीमती सुशीला रोहतगी जी जवाब कुछ इधर-उधर का दे देंगी। मैं उनके सरल स्वभाव से परिचित हूं। वे कुछ न कुछ तो कह ही देंगी, मगर उसका समुचित उत्तर देने के लिए उनको सरकारी पक्ष को छोड़ कर विपक्ष में आना होगा, तभी उसका समुचित उत्तर पायेंगे। वैसे वह रट रटा कर, कुछ न कुछ कह कर उत्तर दे देंगी वैसे ही जैसे कोई कातिल खूनी अपनी सफाई देता है। उसी तरह श्रीमती सुशीला रोहतगी को एक कातिल की तरह अपनी सफाई इस सदन में पेश करनी होगी। मैं आपको दिखाना चाहता हूं सामान्य प्रशासन जिसमें 5 करोड़ रुपया रखा गया है। छोटा सा सुबा, छोटा सा राज्य, मैं समझता हूँ कि बनारस और गोरखपुर कमिश्नरी पूरे पंजाब के बराबर है और उसमें सामान्य प्रशासन पर यह रकम ज्यादा है। जेल पर रकम ज्यादा है और शिक्षा पर रकम कम है और चिकित्सा पर तो केवल 5 करोड़ ही है और स्वास्थ्य के लिए भी केवल 5 करोड़ रखा गया है। तो चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य इन दोनों पर रकम कम है, क्यों ?

श्री शीलभद्र याजी : तगड़े हैं लोग।

श्री राजनारायण : शीलभद्र याजी ने ठीक कहा कि यहां पर लोग तगड़े हैं और इनके घर में लोग तगड़े हैं। यह सब पंजाब में ही हैं। अरे भाई, कुछ तो शर्म खाओ। कृषि सुधार और अनुसंधान की स्कीमों पर कितना है, केवल 65 लाख और कुछ है। तो यह सरकार कृषि के क्षेत्र में भी कितनी उदास है। अगर सरकार सचमुच कृषि क्षेत्र में दत्तचित हो और वह वहां कृषि की उन्नति चाहती हो तो मैं समझता हूं कि आज पंजाब की खेती दुगनी, तिगुनी हो सकती है। लेकिन आज सरकार कृषि की उपेक्षा करती है और दूसरे कामों में इधर-उधर से रकम को खर्च कर देती है और अगर इसी के साथ-साथ देखा जायेगा तो कहा जायेगा कि यह समाजवादी सरकार है।

[श्री राजनारायण]

मुझे अफसोस है कि यह पापी बजट राज्य सभा में पेश करने के लिए भार श्रीमती सुशीला जी को दिया गया है ।

श्री उपसभापति : पेश करने के लिए नहीं, पेश तो गणेश जी ने किया है ।

श्री राजनारायण : जिसकी बड़ी चर्चा है, जिसकी बड़ी शोहरत है और हमारे श्री दीक्षित जी भी यहां बैठे हैं । भारतीय शासकों के प्रिवी पर्स और भत्ते, प्रिवी पर्स समाप्त हो । तो प्रिवी पर्स के पक्ष में बोलने वाले जनतंत्री नहीं हैं । यह दीक्षित जी तमाम चिल्लाते रहे, चिल्लाते चिल्लाते इनका गला रूंध गया, मगर इस बजट में भारतीय शासकों के प्रिवी पर्स और भत्ते के लिए भी करीब 7 लाख रुपया रखा हुआ है । कितना पतन है ।

श्री शीलभद्र याजी : यह राज्य सभा का कसूर है ।

श्री राजनारायण : अब इस समय जो वस्तु स्थिति है, उसका अवलोकन होना चाहिये । जो सरकार प्रिवी पर्स को पाप समझती है—और समझना चाहिये मेरे नुक्तेनजर से—जिस प्रिवी पर्स को लेकर इतना हल्ला मचा, इतना बावेला खड़ा हुआ और मार्च में यह सरकार गठित हो गई, मार्च अप्रैल, मई, जून, चार-पांच महीने बीत रहे हैं, लेकिन अगर प्रिवी पर्स अनुचित है—हमारी दृष्टि में अनुचित है—तो इस सरकार ने उसको सबसे पहले खत्म करने का विधेयक क्यों नहीं प्रस्तुत किया ।

श्री शीलभद्र याजी : आ रहा है ।

श्री राजनारायण : आयेगा । कुछ खबर नहीं है पल की, कौन जाने कल को । यह कह रहे हैं कि आ रहा है, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है । तो इस बजट में भारतीय शासकों के प्रिवी पर्स और भत्ते के लिये लाखों लाख रुपये की व्यवस्था करना सचमुच में किसी भी जनतंत्री सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है और जो सरकार अपने को समाजवादी, समाजवादी, समाजवादी चिल्लाती है उसके लिए कितनी घृणा की बात है, कितनी दुष्टता की बात है ।

देखिये अब अकाल की बात है । 1 करोड़ 15 लाख 1 हजार 200 रुपया पंजाब में अकाल के लिए रखा है । पंजाब में अकाल के लिए गुंजाइश क्यों हो गई । पंजाब में अकाल की गुंजाइश क्यों ? पंजाब में तो अकाल की गुन्जाइश है नहीं । इतनी रकम के रखने की जरूरत क्यों । इसके बारे में भी सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है ।

हमने उत्तर प्रदेश के बजट को अक्सर देखा है, बिहार के बजट को देखा है, राजस्थान के बजट को देखा है, कोई भी बजट नहीं होगा जहां कि उस बजट में हरिजनों के बारे में काफी रकम न हो, मगर इस सरकार से मैं पूछना चाहता हूं जो कि अपने को समाजिक न्याय वाली सरकार तोता रटंत की तरह कहती है कि तुमने हरिजनोत्थान के लिए कितनी रकम रखी, तुमने बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए कितनी रकम रखी तुमने वहां हरिजनों के मकान के लिए कितनी रकम रखी । तुमने वहां जमीन के बटवारे के लिए कितनी रकम रखी, तुमने स्वायल कंजरवेशन के लिए कितनी रकम रखी, तुमने छोटे उद्योग धंधे के लिए कितनी रकम रखी ।

श्री शीलभद्र याजी : तुम-तुम किसको कह रहे हो । चेयर को कह रहे हो ।

श्री राजनारायण : तुम सरकार के लिए कह रहा हूं । चेयर को तो आप कहा जाता है । और तुम तो ईश्वर को कहा जाता है, खुदा को कहा जाता है, हमारे तुम का मतलब सरकार से है ।

तो, श्रीमन्, मैं बहुत ही अदब के साथ यह

कहना चाहता हूं कि बजट वह दर्पण है जिस दर्पण में किसी सरकार का सम्पूर्ण चित्र प्रदर्शित होता है, तो इस बजट में सरकार का सम्पूर्ण चित्र देखा जाय, तो सरकार का सम्पूर्ण चित्र कैसा दिखाई देगा। दिखाई देगा कि कोई अपनी नाक खुजला रहा है, कोई अपना कपार खुजला रहा है, कोई गर्दन पकड़े हुये है कोई पांव पकड़े हुये है, सम्पूर्ण शरीर कोई देख ही नहीं पा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इसमें सम्पूर्ण शरीर परिलक्षित हो और वह सम्पूर्ण शरीर समाजवाद, जनतंत्र का हो। ऐसा बजट यहां पर आये। इस दृष्टि से यदि हम इस बजट को देखते हैं तो यह कितना नाकाफी है, कितना उल्टा है। कितना पीछे-देखू है? इसलिए इस बजट को इस संसद द्वारा, राज्य सभा के द्वारा, पास कराने नहीं दें। ऐसा करना अनुचित होगा, अजनतंत्रीय होगा। मेरे मित्र अगर पीछे-देखू का अर्थ न समझें तो कैसे समझाऊं? इस अवसर पर श्री के० सी० पन्त यहां से चले गए . . .

श्री उपसभापति : आप खत्म कीजिए अपना भाषण।

श्री राजनारायण : श्री पन्त चले गए, हां उनका विषय नहीं है। उन्होंने जब यहां पंजाब के बारे में प्रेसीडेन्ट के प्रोक्लेमेशन को रखा तो उस पर चर्चा की तो दूसरे सम्मानित सदस्यों ने भी चर्चा की आखिर राज्य सभा में या संसद में ऐसे बजट को आने की जरूरत क्या थी? एक राज्य के लिए ससद बजट पास क्यों करे? इस पर बोलते हुये श्री के० सी० पन्त ने सरकार की ओर से एक सफायी दी, एक तर्क दिया कि दलबदल हो रहे थे और दलबदल के लिए उन्होंने कोशिश की कि विरोधी पक्ष को दोषी ठहराया जाए। मैं आपके द्वारा दीक्षित जी से कहना चाहूंगा, वह उम्र में हमसे बड़े हैं, उनका अनुभव ज्यादा अच्छा होगा, मैं उनसे जानना चाहूंगा, दलबदल की प्रवृत्ति कहां से शुरू हुई—किसने इसके लिये उकसाया? श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि सदन के सम्मानित सदस्य इस बात को अच्छी तरह से हृदयंगम कर लें कि 1948 में कांग्रेस को हम लोगों ने छोड़ा, महात्मा गांधी की हत्या के बाद जब कांग्रेस पूंजीपतियों की चेरी हो गई, पूंजीपतियों के पालने में सोने लगी, उन्होंने किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ना बंद कर दिया, तो हमने फैसला किया कि इस प्रतिक्रियावादी कांग्रेस को छोड़ो और समाजवाद की धारा को प्रवाहित करने के लिये आगे बढ़ो . . .

श्री गुरमुख सिंह मुसाफिर (पंजाब) : तो पहले दलबदल आपने की - इसका मतलब यह हुआ।

श्री राजनारायण : हमारे मित्र सरदार साहब, मुझे नहीं मालूम क्यों आज शीलभद्र याजी बनना चाहते हैं . . .

श्री शीलभद्र याजी : आपको दुरुस्त करने के लिए।

श्री राजनारायण : मैं उनसे कहना चाहता हूं, जरा इस बात को देखें कि हम लोगों ने जो 72 के करीब थे उत्तर प्रदेश विधान के सदस्यों में, एक साथ हस्ताक्षर किया मगर जब असेम्बली के मेम्बरों से इस्तीफे का फैसला हमने लिया, क्योंकि उस समय चर्चा चल रही थी कि हम असेम्बली नहीं छोड़ेंगे तो आचार्य नरेन्द्र देव ने फैसला किया, नहीं हम असेम्बली छोड़ेंगे और हम फिर से चुनाव लड़ेंगे, अपने टिकट से चुनाव लड़ेंगे। अगर हम पार्टी छोड़ रहे है तो कांग्रेस के टिकट का भी तिरस्कार करेंगे और जब असेम्बली समाप्त हुई तो केवल 12 आए, जब कि दस्तखत हुए 72 के। उस समय दस्तखत करने वालों में पं० कमलापति त्रिपाठी भी थे, जब उनको बुलाने गए, आओ-आओ घर से तो वह निकले ही नहीं। तो आचार्य नरेन्द्र देव जी और 11 दूसरे लोग कांग्रेस से अलग होने के बाद विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिए और मैं आज बताना चाहूंगा, वह सब

[श्री राजनारायण]

चुनाव लड़े थे, चुनाव में हारे भी। किसी एक मनचले ने कहा : आचार्य जी बड़ी दुखद हार हुई, तो आचार्य जी ने कहा तुम्हारे लिए तो दुखद होगा, हमारे लिए सुखद होगी, अगर मैं नहीं हारता तो हारने वाले को ढांढस कौन देता, जनतंत्र हारने वालों की दृढ़ता पर चलता है, जनतत्र सब्र पर चलता है। अगर हारने वाला उत्तेजित हो जाया करे, अगर हारने वाला घबड़ा जाए तो जनतन्त्र की महिमा गरिमा नष्ट हो जाती है। जनतन्त्र में हार जीत होती रहती है। यह लफंगई का इजहार होता है—हार गए, हार गए—कोई तमाशा है क्या ? यानी, जरा देखा जाय कि कितनी नाजायज हरकतों का इस्तेमाल करके जो दल चुनाव जीतता है, वह भी दूसरे की हार पर खुशी मनाता है। उनको कहना चाहते थे कि जनतन्त्र में हारने वालों की सहनशीलता, उदारता और जनतंत्रीय पद्धति और प्रणाली को मजबूती मिलती है। मैं चाहता हूं कि इस निष्कर्ष को हमारे वे लोग जो हलके तरीके से सदन में बात करते हैं अच्छी तरह से समझें। (इन्टरप्शन्स) श्री याजी ठीक बात कहते हैं। जब चर्चा हो गई है तो सफाई के साथ किसी न्यायालय में जाए, किसी जज को बिठलायें। आज सारे देश में शोर मचा है मत पत्रों में रसायन का प्रयोग किया गया और जनता इसी भ्रम में पड़ी हुई है कि यह बात सही है या गलत है। आज मैं कहने को तैयार हूं।

यहां पर एक मुकदमा चल रहा है श्री शशि भूषण को किसी वकील ने बतला दिया है कि अगर किसी वोटर के नाम से दाखिल करोगे तो अच्छा रहेगा और अपने नाम से करोगे तो फंस जाओगे। अगर वे बलराज मधोक को झूठा साबित करना चाहते हैं तो वे स्वयं दाखिल करें।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर शशि भूषण अपने नाम से मुकदमा दाखिल करें तो फिर मामला हल होता है या नहीं। यह मालूम हो जायेगा उन्हें अपने नाम से मुकदमा दाखिल करने की हिम्मत नहीं है।

श्री उपसभापति : अब आप समाप्त कीजिए। 20 मिनट से ज्यादा हो गए हैं।

श्री राजनारायण : मैं तीन मिनट में समाप्त कर दूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि सत्ताधारी दल को यह देखना चाहिए कि आज उसकी चमड़ी कितनी मोटी हो गई है। वे लोग नाजायज धन सम्भालते हैं, पैसा बटोरते हैं और पद का लालच देते हैं, लोभ देते हैं। पंजाब के एक सरकार को गिराया जाता है और यहां पर लोग हंसते हैं। आज इन लोगों की छाती फूल रही है कि पंजाब की सरकार खत्म हो गई है।

यह सरकार जो यह कहती है कि हम इस देश में से भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे, सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार यह है और यही सारे देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आज जितनी केन्द्रीय सरकार भ्रष्टाचारी है उतनी कोई नहीं है। जो भ्रष्टाचार की गौरव हैं प्रधान मंत्री और मैं अब भी दावे के साथ कहता हूं कि श्री ललित नारायण मिश्र के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने एक जांच कमिशन बिठलाया है। उस कमिशन से इस सरकार ने सारी फाइलें मगा ली हैं। केन्द्र सरकार के इशारे पर रोज राज्य पाल को टेलीफोन होता है कि यह मामला चालू नहीं होना चाहिए। वहा के विधान सभा में मुख्य मंत्री जी ने दो दिन पहले कहा कि इस सबब में फाइलें मंगाई गईं। तो इस दल की सरकार जो आज पापपूर्ण कार्यों में डूबी हुई है वह कहती है दूसरे दल वालों से कि वे भ्रष्टाचारी हैं। इस सरकार ने तो भ्रष्टाचार की सीमा को पार कर दिया है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकारें और केन्द्र की सरकार इस काम में सबसे आगे है। जहां प्रशासन में भ्रष्टाचार की सरिता निकलती है उस

प्रशासन की गंगोत्री केन्द्रीय सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इसलिए आज हर जगह पर भ्रष्टाचार हो गया है। जब ऊपर से भ्रष्टाचार की धारा नीचे को चलेगी तो तेज रफ्तार रहेगी और जब नीचे से ऊपर चलेगी तो फिर रफ्तार कमजोर रहेगी। इसलिए मैं इस बजट को जनहित विरोधी, पंजाब की जनता के हक में न जाने वाला पंजाब की जनता के हितों पर कुठाराघात करने वाला, पंजाब की जनता की जनतंत्रीय और मौलिक अधिकारों को छीनने वाला बजट है, इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं और सदन से अपील करता हूँ कि हरगिज इस को पास न होने दे।

4 P.M.

श्री सुलतान सिंह : उपसभापति महोदय, यह पंजाब का बजट जो सदन के सामने मन्त्री महोदय ने पेश किया है इसके अन्दर मैं चाहता हूं कि जितने मल्टी परपज प्रोजेक्ट्स हैं उनके पूरा करने की तरफ ध्यान दिया जाये। इंडस वाटर ट्रीटी खत्म होने के बाद भी हिन्दुस्तान का पानी पाकिस्तान के अन्दर जाता है। उस का कारण यह है कि हम पोंग डैम मुकम्मल नहीं कर पाये और इसी तरीके से हमने अभी तक थीम डैम को शुरू नहीं किया। पंजाब का किसान जो हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करता है वह बिजली के बगैर तड़पता है, कई कई घंटे बिजली बन्द रहती है, कई कई दिन उसका ट्यूबवैल नहीं चलता है। तो एक तरफ हमारा किसान सफर कर रहा है और दूसरी तरफ देश की जो बेहतरीन दौलत है पानी वह पाकिस्तान के अन्दर जा रहा है। तो मैं आपकी मार्फत सरकार से अर्ज करता हूं कि मल्टी परपज रीवर प्रोजेक्ट्स के लिये ज्यादा से ज्यादा रुपया रखा जाना चाहिए था ताकि पोंग डैम को मुकम्मल करके हम ज्यादा बिजली पैदा करते जिससे पंजाब के किसान और पंजाब के कारखानेदार ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाते और देश का बेहतरीन पानी पाकिस्तान के अन्दर नहीं जाता।

दूसरे मैं आप की मार्फत सरकार से यह भी दरख्वास्त करता हूँ कि हमें खुशी नहीं है यह बजट यहां पर डिसकस करने में क्योंकि यह काम पंजाब असेम्बली का था। लेकिन दुर्भाग्य से पंजाब के अन्दर दो फिरका परस्त पार्टियों ने जन संघ और अकाली दल ने, ऐसी हालत वहां पर पैदा कर दी कि आज यह बजट यहां पेश करना पड़ा। पंजाब की यह बड़ी बदकिस्मती रही है कि वहां दो राजनैतिक पार्टियां जनता को हमेशा लड़ाती रहीं। (व्यवधान) जन संघ हिन्दी भाषा का नारा देता रहा और अकाली दल पंजाबी भाषा का नारा देता रहा और इस तरह ये दोनों पार्टियां वहां के लोगों को लड़ाती रहीं। 1967 के बाद जब जन संघ और अकाली दल के रिश्ते गहरे हो गये तो हम को यह आशा बन्धी थी कि दोनों पार्टियां वहां की जनता को जो भड़काती थीं और लड़ाती थीं वह अब नहीं होगा। जन संघ के लोग संत फतेह सिंह के चरणों में जाकर गिरे थे और उनसे कहा था कि आप तो अवतार हैं, पंजाब में रहने वाले हर हिन्दू की जबान पंजाबी है, आप हम को वजीर बना दो। इस तरह कुछ दिनों तक उनके आपस में रिश्ते चले लेकिन आखिर में वह रिश्ता कुर्सियों के पीछे फिर टूट गया। और वे अलग अलग हो गये। उसके बाद एक डिफेक्शन की लहर चली। हमारे दोस्त राज-नारायण जी ने कहा कि डिफेक्शन की लहर हिन्दुस्तान में कांग्रेस ने चलाई। मैं बताना चाहता हूं कि सब से पहले हिन्दुस्तान में डिफेक्शन राव वीरेन्द्र सिंह जी ने शुरू किया जिनको मुख्य मन्त्री जन संघ ने और दूसरी अपोजीशन पार्टियों ने माना। उसके बाद डिफेक्शन उत्तर प्रदेश में हुआ। मैं यह जानना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह को राज-नारायण जी की पार्टी ने मुख्य मन्त्री माना या नहीं माना, जन संघ की पार्टी ने उनको मुख्य मन्त्री माना या नहीं माना। उसके बाद डिफेक्शन मध्य प्रदेश में हुआ . . .

श्री राजनारायण : श्रीमन्, आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर। मैं आप के द्वारा यह कहना चाहता हूं कि इस सदन में असत्य कहना वर्जित है। मैं चाहता हूं कि यह नियम माननीय सदस्य जान लें कि इस सदन में असत्य भाषण नहीं होना चाहिए। सबसे पहले 1954 में मलखान सिंह को डिफेक्ट कराया गया अलीगढ़ में जो कि हमारे दल से चुने गये थे। उसके बाद डिफेक्ट कराया गया गेंदा सिंह जी को उस के बाद डिफेक्ट कराया गया अशोक मेहता जी को। उसके बाद डिफेक्ट कराया गया थानू पिल्ले जी को और यह सरिता बहाई है जवाहरलाल जी ने। और अब डिफेक्शन का समुद्र बहा रही हैं जवाहर लाल जी की बेटी श्रीमती इन्दिरा नेहरू गांधी।

श्री उपसभापति : ठीक है, अब आप बैठिये।

श्री सुलतान सिंह : यह डिफेक्शन्स की लहर हमारे दोस्तों ने देश में चलायी है और खुला एलान किया कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ कर जो आय उसको हम मुख्य मन्त्री बना देंग और उसके बाद ही यह लहर चली।

श्री राजनारायण : सत्ता को छोड़ कर आये तो क्रान्ति और विरोध को छोड़ कर जाये तो अवसरवाद।

श्री उपसभापति : आप बैठिये।

श्री राजनारायण : जरा हमको समझाने दीजिए। जो लालच से सत्ता में जायेगा वह अवसरवादी होगा।

श्री उपसभापति : आप की परिभाषा वह जानना नहीं चाहते।

श्री सुलतान सिंह : जब यह लहर चली तो पंजाब में ऐसी हालत फिर पैदा हुई और अकाली दोस्त मिनिस्ट्री को छोड़ छोड़ कर बाहर आये। एक अकाली दल के दो अकाली दल बन गये और जनसंघी अपने पुराने नेता गुरनाम सिंह की तरफ देखने लगे और कभी सन्त फतेह सिंह की तरफ देखने लगे। मैं यह मानता हूं कि गवर्नर साहब ने जल्दबाजी की। मैं यह मानता हूं कि गवर्नर साहब को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी राष्ट्रपति के सामने, लेकिन पंजाब में जो राष्ट्रपति राज हुआ, वह करके वहां के गवर्नर ने वहां की जनता की बड़ी खिदमत की है। मैं नहीं चाहता था कि यह बजट इस हाउस में डिस्कस हो। यह प्रजातन्त्र का दुर्भाग्य है कि वहां की असेम्बली जिस काम को करती उस को हम इस हाउस में कर रहे हैं लेकिन जो हालात बन गये थे उनमें इस को कोई रोक नहीं सकता था। तो मैं आप की मार्फत सरकार से प्रार्थना करता हूं कि यहां इस हाउस के अन्दर एक पंजाब रिआर्गनाइजेशन ऐक्ट पास हुआ था जिस में पंजाब और हरियाणा के लिये अलग अलग प्रदेश बने थे। उस रिआर्गनाइजेशन ऐक्ट की तहत कुछ फैसले हुए थे उनमें एक यह था कि पंजाब के अन्दर जितने नहरों के हेड वर्क्स हैं, उन पर भारत की सरकार का कंट्रोल होगा और पानी का बटवारा भारत की सरकार करेगी। लेकिन हरी का पत्तन, रोपड़ हैडवर्क्स आज भी जो हैं उन पर पंजाब की सरकार का कब्जा है। अब तो पंजाब में अकाली राज नहीं है। अब वहां आप का राज है और जो रिआर्गनाइजेशन ऐक्ट यहां पास हुआ है मैं चाहता हूं कि आज आप उस रिआर्गनाइजेशन ऐक्ट को इम्प्लीमेंट करें। उसके साथ साथ मैं एक और अर्ज करना चाहता हूं कि फाजिलका और अबोहर के बारे में फैसला भारत सरकार ने किया था। भारत सरकार के फैसले के बाद फाजिलका और अबोहर के लोगों को अकालियों ने इतनी बुरी तरह से रौंदा कि उन्होंने वहां के सारे विकास के काम बन्द कर दिये। वहां के बिजली के खम्भे उखाड़ दिये, तार तक काट दिए गये और वहां दो साल के अन्दर फाजिलका के लोगों के लिए कोई विकास का काम नहीं हुआ। मैं चाहता था कि आज राष्ट्रपति शासन के अन्दर

सरकार उस फाजिलका और अबोहर के पिछड़े हुए लोगों की तरफ खास तवज्जेह दे । मैंने जब बजट को पढ़ा तो मुझे बड़ा सदमा हुआ कि एक तरफ चंडीगढ़, जो पंजाब में जाना है, उस के लिए भारत सरकार 10 करोड़ रुपया, उस के विकास के लिए खर्च करती है और फाजिलका और अबोहर, जो पंजाब से हरियाणा को आना है, उस पर एक कौड़ी भी खर्च नहीं होती है । तो एक तरह से चंडीगढ़ को . . .

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON : Sir, on a point of order. It is a well-accepted thing that this House should not be utilised to fan regional animosities and communal passions. Now, the hon. Member, speaking in the name of Punjab, is trying to fan anti Punjabi feelings in this House among the Haryana people. Is it correct ?

SHRI SULTAN SINGH : I am speaking on Punjab.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Please continue your speech.

श्री सुलतान सिंह : तो जनाब मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा था कि फाजिलका अबोहर का इलाका जो कि भारत सरकार के एवार्ड के तहत हरियाणा को आना है उसके अन्दर कोई विकास का काम होता नहीं और चंडीगढ़ जो कि पंजाब को जाना है उसके विकास के लिए 10 करोड़ रुपया हर साल खर्च किया जा रहा है । मैं समझता हूं कि यह उस इलाके के साथ बड़ी जबरदस्ती है, मैं हरियाणा के लोगों के साथ नहीं कहता बल्कि यह कहता हूं कि उस इलाके के लोगों के साथ इनकी ज्यादती है । इसके साथ साथ यह है कि वहां की जबान हिन्दी है और वहां के लोगों को अपनी जबान के माध्यम से पढ़ने की, अपनी जबान के माध्यम को चुनने की, इजाजत नहीं है, उनपर जबरदस्ती पंजाबी थोपी गई है । मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आज गुरनाम सिंह की सरकार नहीं है, आज बादल की सरकार नहीं है, आज सत फतेहसिंह की नहीं चलती तो कम से कम आपको यह चाहिए कि ऐसा करें कि लोग अपनी भाषा के माध्यम को चुन सकें ।

इसके साथ साथ मेरी एक दरख्वास्त और है और वह यह है कि मैं नहीं चाहता कि वहां पर हम राष्ट्रपति शासन लम्बे अर्से के लिए रखें तो मेरी आपके मार्फत यह दरख्वास्त है कि पंजाब की जनता को जल्दी से जल्दी अपनी असेम्बली चुनने का अख्तियार देना चाहिये और वहां पर चुनाव अक्टूबर या नवम्बर के अन्दर अन्दर जरूर हो जाना चाहिए । जब मैं पढ़ता हूं कि चुनाव फरवरी में होंगे तो मैं समझता हूं कि पंजाब की जनता के साथ यह बड़ी ज्यादती है ।

इसके अलावा एक चीज मैं और आपसे कहना चाहता हूं और वह यह है कि आज पंजाब तीन नये पैसे युनिट के हिसाब से बिजली दिल्ली को डी०एस०यू० को देती है और वही डी०एस०यू० वह बिजली उत्तर प्रदेश को 9 पैसे यूनिट के हिसाब से देती है । तो डी०एस० यू० रकम बनाती जा रही है, दिल्ली के लोग पैसे कमाते हैं और उस पंजाब में जिसने कि बिजली पैदा की – इसमें पंजाब और हरियाणा दोनों शामिल हैं – जिसने सारे हिन्दुस्तान में इतना बड़ा प्राजेक्ट खड़ा किया वहां पर किसान बिजली के लिए तरसता है । तो मेरी आपकी मार्फत भारत सरकार से प्रार्थना है कि जिस तरह से पंजाब हरियाणा के अन्दर बिजली में कट लगा है उसी तरह से दिल्ली में भी कट लगना चाहिये ताकि मन्त्रियों को पता तो लगे कि बिजली के बगैर कितनी दिक्कत होती है ।

तो इन शब्दों के साथ मेरी खास तौर पर दरख्वास्त है कि फाजिलका अबोहर के विकास के लिए किया जाय, बच्चों की पढ़ाई के माध्यम को, इसके फैसले को, उनके वालदेन पर छोड़ा जाय, इसका फैसला उनके माता पिता को करने दीजिये । साथ साथ जो रिवर प्राजेक्ट हैं उन पर ज्यादा से ज्यादा पैसा रखिए और जो हेड-वर्क्स हैं उनपर अपना कब्जा करिये । और खुदा के वास्ते जनसंघी और अकालियों से जो सारी

[श्री सुलतान सिंह]

जिन्दगी पंजाब को लड़ाते रहे इनसे जो अब छुटकारा मिला है तो जल्दी से जल्दी चुनाव करा दीजिए ताकि इनकी छुट्टी सदा के लिए वहां से हो जाय। धन्यवाद।

(Shri Bhupesh Gupta stood up)

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You want to speak ?

SHRI BHUPFSH GUPTA : I thought I would like to. What do yon want me to do ?

MR. DEPUTY CHARIMAN : You can speak on the Appropriation Bill.

SHRI BHUPESH GUPTA : That is all right. Let me speak.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : It is quarter past tour now. I shall call the Minister.

SHRI BHUPESH GUPTA : Do not get upset by it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : 1 do not know, normally we sit up to six, we may have to sit beyond six.

SHRIMATI PURABI MUKHOPA-DHYAY (West Bengal) : Sir, I am on a point of order. In the Business Advisory Committee there are Members of different parties. May I know from the Members why, if they thought that this Punjab Budget was such an imprortant thing, they did not in that meeting ask for time so that they can continue to speak for hours and hours together ? What is the utility of having a Business Advisory Committee here and what is the sanctity of any time allocated by the Business Advisory Committee if we are ready to break all the rulei ? Then you need not have to invite any Business Advisory Committee meeting in future.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं श्रीमती मुखर्जी की सलाह से सहमत हूं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को खत्म कर दिया जाना चाहिये। यह तो गला घोटू कमेटी हो गई है।

श्री महेश्वर नाथ कौल : यू० पी० में यह नाम है।

श्री राजनारायण : हमने ही यह नाम वहां रखा था। इसको गिलोटिन कमेटी मत बनाइये। इसीलिये हम इस कमेटी में कभी गये ही नहीं।

SHRI BHUPESH GUPTA : Our friend, Shrimati Purahi Mukherjee, is slightly late in this matter. She is always la[f]e but she specially late in this matter because already we have exceeded the time, and the so-called recommendation of the Business Advisory Committee has long been buried. Now we are in the midst of a new decision which has been evolved in the House through your co-operation, Mr. Deputy Chairman. Now, not a tear will be shed that the communal and reactionary Badal Ministry has fallen in Punjab. I do not think that even the broad masses who supported that Ministry would be very sorry that it is no longer in existence The record of this Ministry is one which can only cause shame, '· disappointment, sorrow, anger and revulsion among the people. What will happen to Punjab we do not know. The President's rule has to go some time or the other, the sooner the better. But unless the democratic and the left forces in Punjab could come together and build up a new fighting front, basing themselves on the demands of the agricultural labourers, the Harijans, the industrial workers and the urban poor, I do not s.'e any future for Punjab. It will be a sort of arrangement between tweedledum and tweedledee, depending upon who gets the upper hand in organising defections or any other political manipulations. Therefore, the moral of Punjab politics is this that the political centre of gravity must shift, to the villagers and the industrial workers, whatever they are, in order to build up a truly left-oriented mass movement, so that it can take its place in the political life of Punjab.

Now, Sir, I would make certain suggestions for tne Governor or the Governor's regime to consider. I hope that as many of them as possible will be implemented. I think everyone of them can be implemented. First of all, I must point out to this House jthat there are many loopholes in the existing

lard laws in Punjab and they have been deliberately keit by the successive Ministries that came into existence It is necessary to plug all these ioopholes and withdraw, in particular, the exemptions from the ceilings fixed for the landlords. These exemptions have become a source of subversion of the ceiling law as a whole. The ceiling law has been made nonsense on account of these exemptions which have enabled the landlord class to retain large areas of land concentrated in their hands. So the exemptions must go.

Then, Sir, Government and other employees in Punjab have many grievances and they come up again and again in the form of agitations and otherwise. 1 think these grievances should be seriously looked into with sympathy and consideration. There should be an inquiry into the charges against the ex-Ministers and Class 1 officers. Punjab has been a cockpit of corruption under the Akali rule ; nepotism and favouritism literally ran riot and there were no norms which were observed in the matter of public policy or administration. 1 think this matter has to be seriously gone into.

As far as land laws are concerned—I again revert to them—the Punjab Security of Land Tenures Act of 1953 should be repealed. This has proved harmful. And similarly, the loopholes in the Pepsu Tenancy Act of 19 >5 should be plugged by a radical amendment of that Act. Government waste lands should be distributed among the agricultural workers and poor peasants, especially the Harijans. in Punjab. Punjab politics have been dominated by certain sections of the rural rich who have some time supported the Congress politicians and very often the Akali politicians Therefore, ever from a political and social angle, it is necessary to see that the land is redistributed, especially amongst the agricultural labourers. Poor, who are in cultivating occupation of evacuee land, should be granted ownership on payment of nominal charges. That, again, is very importent. Surplus land, including those vacated by the officers and other rich persons, should be distributed among the Harijans as early as possible. The Birla farm lease was cencelled. The decision to that effect should be implemented.

The suboninate services and the roadways workers have many grievances in respect of interim relief, bonus, romoval of anomalies in their pay scales. They have also complamed of indiscrimination and vindictiveness towards them. These complaints should be carefully gone into and the Governor should set the record straight.

The Akali Government followed a policy of communalism, favouritism and nepotism in the matter of appointments. Now that the Akalis are out of office, the Government should re-examine all the necessary files and papers and remove all traces of corruption, nepotism and favouritism indulged in by the discredited Akali Ministry.

Effective steps should be taken to curb crime. In Punjab the policemen are guilty of committing crime. They freely commit, murders, freely raid homes and do all kinds of things. They commit many illegal acts. Who is going to control the uncontrolled Punjab police ? Now that Punjab is under the Central rule, somebody in the Central Government should wake up and see that this police is tamed a little so that it becomes human and civilised in behaviour.

Under the Akali rule the Harijans were the special victims in the hands of their rulers. Enquiry should be ordered into all these allegations of victimisation of the Harijans. Even now Harijans are socially boycotted. I think this is illegal also. Attack on Harijans should be a cognizable offence and those practising untouchability should be given deterrent punishment as a matter of social policy.

Increase in minimum wages is substantially called for not only for the various industrial workeis but also for agricultural workers. That should be one. A number of mills and factories are closed in the Punjab today. They should be reopend. The mill like the Hindustan Embroidery Mill of Amritsar should be taken over by the Government because this has been closed for a number of months causing great hardship to the workers. Meanwhile the industrial workers should be given some relief to relieve them of their suffering as far as possible. The housing scheme for the industrial workers suggested by some people should be finalised and implemented. Recently, Sir, under the Badal Ministry the medical colleges increased their fee. This increase in fees should be cancelled and the old position restored. Drinking water and irrigation facilities should be made available in submountanous areas.

[Shri Bhupesh Oupla]

Finally, Sir, a number of cases of workers are pending. The'e cases arose out of agitation of the agricultural workers, industrial workers, government employees and other sections of the toiling people. These cases should be withdrawn. These are some of the concrete suggestions that I have made for the Government to consider.

Before I sit down, just one or two words. . .

SHRI ARJUN ARORA (Uttar Pradesh) Only ore or two ?

SHRI BHUPESH GUPTA : One or two not in the literal sense. ! am aware she is taking down notes. I am glad I can pass on my notes to her. . ,

SHRIMATI SUSH1LA ROHATGI : I am always alert during your speech.

SHRI BHUPESH GUPTA : Much has been said about the President's Rule. U n fort una ely. President's rule had to come. Tie Governor has dissolved the Assembly. We cannot hang in the air. Fither ilere is an Assembly ard normal rule in the State or there is President's rule. There is no *via media.* So, President's rule has to come whether you like it or not 11 e point is, what use you make of the President's rule We can use it for all kinds of nefarious purposes cr we can use it for doirg serrethirg good, at least to purify scire aspects of Punjab administration and pi Hie life. I have m\ doubts about what this Government will do. As you know very well, they are not interested in this. .They do not even want to listen to what we have to say. That is why they bring this BM and want to push it thiough without even a discussion, if possible.

Now, as far as the Governors are concerned, n,y friend Mr. Pant, referred to this ques ion He is not here now. I am sorry that l.e is toing to imitate his father in some respects without having either the maturity of his age or the gift of mature age. But all the same, he is trying to do it, and it is good sometime;, that he should do it. /Sow, as far as the Governors are concerned, many ptopJe demand that this institution should be abolished. It is an absolutely useless, repulsive, expensive, ridiculous institution that we are maintaining, an institution of super-annua'ed roliti-chns or ICS officials who after retirement must be provided some position ; he:ice the doors of the Raj Bhavan must be kept perpetually open for them. I think this post should be abolished. Why maintain this post ? What are they ? I can understand if you want some show. But what useful function are they fulfilling? If they have only to sign some papers, well, we can work out some machanism to deal with such things.

SHRI ARJUN ARORA : Are you advocating elected Governors ?

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra) : Install a computer for signing.

SHRI BHUPESH GUPTA : You can abolish this post to begin with. Why do you need Governors at all ? The States can have their own arrangements to hand e such matters Formalities can be dore by other agencies which we can create. The Speaker, for example, can sign the final Bill and then it can become law. The Governors should not be there. First of all it is expensive Senondly, it is os'.entatious. Third.y, it is a source of political corruption. Fourthly, it is a receptacle for all discredited politicians and ifficials. Sir. I think the Congress Puny has to take it up serious y tl at no ICS officer after retirement should be made a Governor. It is an insult to our parhamen-taiy system. A Governor bccot.es the head, in a limied sphere, ol a parliamentary institution, when belorc retuen tr.t he was under the legislatuie. Besides, it is also veiy wrong otherwise I need not go into that. Therefore, Sir, this post should be abolished. It has bio me an ageney sometimes of the intelligence Department, sometimes of the Home Ministry, sometimes of warring groups of politicians, sometimes of families, sometimes of business concerns ; I do not know what they are. What the :moody Governors will do, nobody knows. ; How they will behave, nobody knows, because we have not even laid down proper norms of behaviour fo.' them. And we are told that the Governors will decide as to jwhat should be their function and ho.* thoy 1 will behave. Sir, il is like asking delinquent

chi'dren in the reformatory school to lay down rules for their behaviour. It is like asking the bandi s to lay down their ru es or norms.

It ˙s like askir g tie corrupt people to lay down rules for proper behaviour. I am not saying that the Governors are necessarily corrupt. But yo i cannot ask them to make rules. They are u> fit to do so. They will like to hang on to their position. They have developed such l fascination for this post that they cannot overcome it at all So, 1 think we should seriously consider this matter

As far as defection is concerned, Sir, a Bill should be buught Why is the Govern rr.ent not bringing this Bill ? 1 cannot understand. A CO nmittee was formed with a lot of fanfare. E\ery party had representation on that committee to represent the party's point of view. And the cemmittee came to certain unanimous conclusions also. Let the n be implemented. When a'.l the parties on the Committee agreed— there were also men like Shri Ja>a-prakash Narayan ind others on the Committee—what is the I itch in fringing forward that measure ? What is the reason for dealyin^ that matter ? I say it is being deaved because the Cenral Government does noʳ like the »ize of the Ministry at the Centre to be curbed. The size of the Ministry should not e>ceed 10 per cent of t: e membership of the Legislature. That was the recommendation. Mr. Chavan sad, "No, it should nut apply in the case of the Certre because we are more Ten per cent is too sn all a proportion for us." For Assam he was ready, for Rajasthan he was ready, but when it came to the Centre, he wanted to have a fiee hard, at least as much leeway as possible in order to put in as many people as possible in (he Council of Ministers. I have no quariel with individual Ministers as such who belong to the Council of Mmhteis. but why should it be like that ? The Cenue should set an example and say, we will have 10 per cent. Why cannot they do it 7 What is the diftkulty ? Some of the Ministers are utterly useless, utterly useless, if 1 may say so. I do not know what they are doing, Some are good, may be, I rom their own point of view. There is r.o pi hey direction. There is no orientation in Government's policy. You cannot just parade Ministers as a bunch of political mininisis and teil the world that social measures are giong to be taken. We do not want political minikins, I tell you very frankly. A Council of Ministers shall he based on a clear thought and policy direction which would be spelt cut in concrete terms, whether in terms of nationalisation of foreign monopoly or in terms of concrete action or in terms of measures which conform to the interests and demands of the people. But nothing of the kind do we have. Are we doing any such t ing to tell the world that we are going forward ? Tomorrow or the day after they will come with Maintenance of internal Security Bill, a shameless Bill, a shameless act on the part of the Government. We sliall come to that, But this is how the Government is behaving. Three months have passed after the election, March, April, May and June, nearly four months. How much is 'here to our credit ? Nothing at all. Nationalisation of insurance shou.d have been done twenty years ago. The Government was committed to it ten years ago and it has been done now. What about amendment of the Constitution ? Nothing of the kind has been done. Nothing of the kind is being done. Therefore, you do not need a Ministerial parade. All J say is the number can be reduced very easily. J understand, Sir, you are happy because the wages of certain institutions under the canopy are going to be increased. If I were in such a position I would have been happy too. You see what they ha\e done. They have doje many things contrary to the mandate of the election. Again and again we shall den.and, again and again I shall tell this Government, well, they may think today that ti.ey tan get away liki that, but the people will not allow them. It does not tase **tne** reople long to realise that once tne mandate is violated, the Government has to be dealt wnh accoidingly. 1 do not want anybody, to be dealt wiih harshly. But how is it that the first part oi the budget Session is coming to an eiid now and we have not a single matter wnicn we can present to the nation as something solid, something radica , something in accordance with the spirit of the eicc.o.al mandate *!* On the contra y, this Government ij insulting this House by pioducmg oeioie us the Maintenance of Internal oceuri.y bill, wed, this is the way ol political treacnery. 1 s-y so ; and I think the Ciovernmeiu snouid oe ihoioughly condemned on uiai accou.it. 1 can say many tilings ajout ru.ijab. 1 Have to speak because 1 must maice eerwiu

[Shri Bhupesh Gupta]

suggestions. I do not have any hope that tl is Government will do any such thing. Once again I condemn the attitude of this Government. I do hope that the Government would realise that they have to speak in the language o*f* action, not in the mere eloquence of certain speeches here and there. Certainly they have to project an image not by sending Ministers abroad throughout the world but by doing something solid at home. Uiiless you ate strong at home, doing something concrete at home, people will not take you seriously. We are making our Ministers a laughing stock. I am told that tomorrow morning some Ministers will be going around the world to tell the vorld that Pakistan is killing democracy. But tomorrow in this very House they shall biing a Bill and have it passed, thus paiticipating in this slaughter of democracy. . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You can say all this tomorrow.

SHRI BHUPESH GUPTA : Now you are also impatient. . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN : When that BilJ comes you can speak. . .

SHRI BHUPESH GUPTA : You have spoken for ten minutes. You have taken ten minutes . . .

MR. DEPUTY CHARMAN : Please sit down. I have called Shri Tohra.

SHRI BHUPESH GUPTA : 1 will request the hon. Minister through you to convey my suggestions to the Punjab Governor and also to the Home Minister and Prime Minister who deal with Govenors and to ensure that the proposals I have made are seriously heeded and are implemented. They are capable of implementa tion here and now. 1 have nothing against Shiimati Sushila Rohatgi who has been nice to us and I hope she will continue to be so. When such bad Bills come, she should not be present here to corrupt herself politically.

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा (पंजाब) : माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं जो पंजाब का बजट पेश है उसका आम तौर पर स्वागत करता हूं। वह क्यों? वह इसलिये कि कम से कम इस बजट में किसी नये कर का प्रस्ताव नहीं है जैसा कि केन्द्रीय बजट में जनता के ऊपर, गरीबी हटावो का नारा देकर भी, दो-ढाई अरब के कर लगाये गये हैं। कम से कम सरकार ने यह अच्छा ही काम किया कि पंजाब के बजट में कोई कर नहीं है। 1967 ई० का जो चुनाव हुआ था उससे लेकर 15 जून, 197। तक, थोड़े समय को छोड़कर, पंजाब में किसी न किसी रूप में अकाली दल का शासन रहा है और यहाँ बहुत से मेम्बरों ने अकाली शासन की चर्चा की लेकिन मैं हर आइटम में इनको बता देना चाहता हूं कि अकाली शासन जो है वह कांग्रेस के 20 साल के शासन से कहीं बेहतर है। किसी आइटम को आप लीजिए। यहां कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि जो इम्प्लाइज हैं, जो कर्मचारी हैं उनको इन्टरिम रिलीफ नहीं दी गई लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि बीस साल कांग्रेस वालों का पंजाब में राज्य रहा और और वहां क्लर्क की जो भर्ती होती थी वह 60-4-100 में होती थी और अकाली शासन में वह बढ़ कर 110-10-250 हो गई, स्कूल टीचर की जो भर्ती होती थी वह कांग्रेस राज्य में बीस साल तक 60-4-100 रही लेकिन अकाली शासन में मुझे फख्र है कि अगर किसी राज्य में कोठारी कमिशन की तमाम सिफारिशें लागू की हैं तो वह पंजाब में की हैं, अकाली शासन ने सबसे पहले उसे लागू की हैं और आज वहां टीचर की भर्ती जो है वह 125 रु० से आरम्भ होती है। यहां तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पीयन्स है इनका ग्रेड 70-1-80 है लेकिन पंजाब में पीयन्स का ग्रेड है 70-2-80-3-95। दस साल में वह 95 रुपये में पहुंच जाते हैं। केन्द्र से कहीं बेहतर है। इसका एक जिन्दा सबूत है कि हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी थी तो वहां के इम्प्लाइज ने आन्दोलन किया कि चूंकि आन्दोलन सेंट्रल गवर्नमेंट के

खिलाफ था तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही थी कि सेंट्रल ग्रेड ले लो, लेकिन उनका जवाब था कि सेण्ट्रल ग्रेड नहीं चाहिये, पंजाब ग्रेड चाहिये। इसलिये यह जिन्दा सबूत है कि पंजाब में एम्प्लाइज से कोई बेइन्साफी बीते समय में नहीं हुई है, बल्कि पंजाब की अकाली सरकार को यह पक्ष है कि हमने एम्प्लाइज की तनख्वाहों में बहुत बढ़ोत्तरी की। सरदार प्रताप सिंह कैरों के राज के वक्त पंजाब के किसानों के ऊपर खुशहाली टैक्स लगा था, उस खुशहाली टैक्स का 29 करोड़ रु० बकाया था और कम्युनिस्ट भाइयों ने और पंजाब के किसानों ने वहां बड़ा भारी आंदोलन किया, कई किसान शहीद हुए, उन पर अत्याचार हुए और उनको जेलों में भरा गया, लेकिन कांग्रेस ने सरकार ने वह खुशहाली टैक्स नहीं छोड़ा। अकाली दल की सरकार ने जो करीब साढ़े 29 करोड़ की बकाया रकम थी, उस पर कलम फेर दी, इसके अलावा कोई नया कर नहीं लगाया। अंग्रेज के राज में और कांग्रेस के राज में जितनी सड़कें बनीं, 20 साल के कांग्रेस राज में और 100 साल के अंग्रेस के राज में, 120 साल को जमा करें तो जितनी सड़कें बनी हैं 120 साल में, पिछले 4 साल में उनसे कहीं ज्यादा सड़कें बनी पंजाब में।

हरिजनों के बारे में अभी भूपेश गुप्त जी ने कहा और बहुत से लोगों ने उनका सवाल उठाया। जो पंजाब को नहीं समझ पाते और यहां कहते हैं हरिजनों पर अत्याचार करते हैं, उनको मैं बतलाना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से हरिजनों के बारे में जो रिपोर्ट अभी तक छपी हैं, उन रिपोर्टों को पढ़ने से पता चलता है कि पंजाब ही ऐसा राज्य है, जहां छुआछूत सबसे कम है। पहला राज्य है पंजाब और दूसरा जहां सबसे ज्यादा है वह महात्मा गांधी का राज्य है, गुजरात और दूसरा राज्य है जहां उससे कम है छुआछूत वह है हमारे प्रधान मंत्री का सूबा उत्तर प्रदेश।

और जो पंजाब में खेत मजदूरों के वेतन की बात करते हैं, उन भाइयों को शायद किसी को पता नहीं है—मैं भी एक छोटा सा किसान हूं और मैं दावे के साथ यह बात कह सकता हूं—जितना खेत मजदूरों का वेतन पंजाब में है उतना किसी स्टेट में नहीं है और आज पंजाब में 4 रु० हैं, कहीं तो 6 रु० भी हैं—चार रुपये से छः रुपये रोज और रोटी चाय वगैरह सब किसान देता है मजदूर को। और ऐसी कोई समस्या वहां पर नहीं है। हमारे कांग्रेस वालों ने, जब उड़ीसा में गवर्नरी शासन था, तो वहां खेत मजदूरों का वेतन नियत किया था 2 रु० से ढाई रु० तक। लेकिन बातें वह पंजाब की करते हैं, जहां 6 रु० रोज खेत मजदूर लेते हैं।

इसी के साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूँ, यह सारा पंजाब ने अपनी हिम्मत से किया, इसमें केन्द्रीय सरकार की कोई मदद नहीं है। हमारे भाई सुलतान सिंह जी ने कहा कि बिजली की कमी है। मैं तो ऐसा देख रहा हूं कि हमने जो पिछला लोक सभा चुनाव लड़ा था, दूसरों के साथ हमारी नीतियों में ज्यादा मतभेद नहीं था और अगर ऐसा होता और गुप्त जी के मुताबिक अगर हम रिएक्शनरी होते तो हम राष्ट्रपति श्री वी० वी० गिरी को क्यों वोट देते। हमने और जो हमारे अकाली दल के दो साथी थे, उन्होंने प्रिवी पर्स के खात्मे के लिए भी अपना वोट दिया था। हमारे गुरु जी ने सिखाया है : नाम जपना वन्ड छकना — परमात्मा का नाम लेना और बांट कर खाना। हमने जो लड़ाई लड़ी पंजाब में वह इसलिये क्योंकि केन्द्रीय सरकार पंजाब के साथ बेइंसाफी करती आ रही है। मैंने यहां एक सवाल किया था कि आज तक सरकारी क्षेत्र में कितनी इंडस्ट्री लगी हैं, तो जवाब मिला 6,555 करोड़। तो मैंने पूछा था पंजाब में कितने की लगी हैं, तो जवाब मिला 32 करोड़ रु० की। अगर हम आबादी की गिनती का हिसाब लगायें तो 500-600 करोड़ के दर्मियान बनता है और 32 करोड़ की भी वह फैक्टरी है पंजाब में जिसको

[सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा]

कहते हैं सफेद हाथी ...(*Time bell rings*) डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं एक ही पंजाबी इस मसले पर बोल रहा हूँ। पहले जो बोले दूसरी स्टेटों के भाई थे। हमें टाइम मिलना चाहिये।

श्री उपसभापति : आपको 12 मिनट हो गये।

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : 12 मिनट नहीं, हमें 30 मिनट चाहिएं। आपने उनको टाइम दिया जो पंजाब के बारे में बोलते-बोलते इन्टर्नल सिक्योरिटी की बातें करते हैं। मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, मैं ही एक पंजाबी मेम्बर बोल रहा हूं, मेरे कांग्रेसी भाइयों ने पंजाब की बात भी नहीं कीं, कोई हाजिर भी नहीं है।

श्री राजनारायण : बोलने दीजिये। हमारा समय इनको दे दीजिये।

श्री उपसभापति : आपने तो अपना समय खत्म करके दूसरों का भी समय खत्म कर दिया।

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : मैं यह कहना चाहता हूं कि सेन्टर ने हमारे साथ बितकरा किया है। इलेक्ट्रिसिटी के मसले में 32 करोड़ की जो इन्डस्ट्री नांगल में है वह आधी बिजली रोज खाती है। हम कहते हैं उठा लीजिये, हम बिजली से किसान के ट्यूब-बैल चलायेंगे, पैदावार बढ़ायेंगे। मैं यह बात भी फख्र के साथ कहता हूं 20 साल कांग्रेस के पास पंजाब रहा और वहां के बजट से पता चलता है वहां की पैदावार 30 लाख टन थी। लेकिन इस बजट में जो निशानें दिये गये हैं वे 70 लाख टन के हैं। यह फख्र हमको ही है कि हमने किसानों को तैयार किया। इनकी तरह काम नहीं किया; क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने तो किसान के ट्रैक्टर और ट्यूबवैल और उनके स्पेयर पार्ट्स के ऊपर टैक्स लगा दिया है, डीजल के ऊपर टैक्स लगा दिया है और इस तरह से यह सरकार पैदावार बढ़ाने की बजाय घटाने की बात करती है।

हमने किसानों को उत्साह दिया और इस उत्साह से मुतासिर होकर पंजाब के एक छोटे से सूबे के किसान ने भूखे भारत को अन्न दिया और इतना अन्न दिया जो केन्द्र से उठाया नहीं जा रहा है। आज उस अन्न को उठाने की इस सरकार में अहलियत नहीं है और वह सारा अन्न प्लेटफार्मों में रूल रहा है, तो मैं यह बिनती करूंगा कि हमारे साथ बितकरा किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जो आरोप मैंने लगाये हैं उनकी कोई तरदीद नहीं है। रावी नदी के ऊपर जो थीन डैम बनाया जाना था वह अभी तक नहीं बना, उसका पानी पाकिस्तान को जा रहा है और उसको रोकने की कोई चिन्ता नहीं है। यह पंजाब के साथ बितकरे की बात है।

हमने पिछले साल 14 फरवरी को डा० राव से मुलाकात की। पंजाब के जो एम० पीज० हैं, उन्होंने उनके साथ मीटिंग की और उनसे कहा कि सरकार यह काम शुरू कराये। दुश्मन मुल्क को 100 करोड़ रुपया दे दिया है, लेकिन फिर भी पानी इस तरह से जा रहा है और बेकार जा रहा है। वहां पर रोजन 200 मेगावाट बिजली पैदा होगी उस डेम के बनने से। पानी से ज्यादा बिजली की जरूरत पूरी होती है। हमने डा० राव से कहा कि इसके बारे में आज्ञा पत्र दे दीजिये, पंजाब सरकार को इजाजत दे दीजिए और पंजाब सरकार कर्जा लेकर यह काम शुरू कर देगी। भटिन्डा में जो गुरुनानक थरमल प्लान्ट बन रहा है, उसके लिये भी उन्होंने इजाजत नहीं दी थी। हमने बगैर आज्ञा के वह काम शुरू कर दिया और आज्ञा बाद में आ गई। इसलिये मैं समझता हूं कि यह सरकार पंजाब को जकड़ कर रखना चाहती है और उसको आगे बढ़ने देना नहीं चाहती है। इस सरकार में क्योंकि हिम्मत नहीं है, यह उत्तर प्रदेश को आगे नहीं ले जा सकी, यह

मध्य प्रदेश को आगे नहीं ले जा सकी और चाहती है कि दूसरे आगे क्यों जायें। इनका समाजवाद का लक्ष्य उल्टा है। यह देश के करोड़ों लोगों को रोटी कपड़ा और मकान दे नहीं पाते और इनकी भावना है कि जिनके पास यह चीजें अपनी हिम्मत से हैं, उससे छीन ली जायें। सब एक जैसे नंगे भूखे हो जायेंगे, समानता आ जायेगी।

इसी प्रकार में हमारे ऊपर बिजली का संकट आया, किसानों का गेहूं बाहर वर्षा में भीगता रहा और हमने इलतजा की इनके पास यहां आकर के कि तुम यहां पर फुव्वारे चला रहे हो एयर कंडिशनर चला रहे हो, उनको तो कम से कम बन्द करो। अगर इन चीजों को बन्द कर दो तो किसान गेहूं निकाल लेगा, क्योंकि किसान ने सरकार से कर्जा लिया हुआ है। आज आप पंजाब के किसान की बात पर हंस कर कह रहे हो कि वह टैरालीन पहिनता है, पंजाब का किसान खुशहाल है। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि पंजाब के किसान के ऊपर 70 करोड़ रुपये का कर्जा है। पंजाब के किसान का स्वभाव इस तरह का बना हुआ है कि वह चढ़ती कला में रहता हैं, वह कर्जदार हो, किसी भी हालत में हो, वह माड़ा पहिनता नहीं, माड़ा खाता नहीं, यह उसका एक स्वभाव है। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, जिससे किसान का गेहूं निकालने के मामले में बहुत नुकसान हुआ है।

अब फाजिलका और अबोहर की बात कही गई है, मैं समझता हूं कि पंजाब के बजट के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे भाई का वह आरोप बिलकुल गलत है। फाजिलका और अबोहर में भी उसी तरह से सड़कें बनी, जिस तरह से और इलाकों में बनीं। वहां पर उसी तरह से स्कूल बनें जिस तरह से और जगह पर बनें। उस इलाके की वैसी ही तरक्की हुई जिस तरह से और इलाकों की हुई। फाजिलका और अबोहर का कोई भी इलाका हम किसी को देने के लिये तैयार नहीं हैं और पंजाब इस बात के लिए आन्दोलन करेगा। यह जो आरोप है बिलकुल गलत हैं और यहां पर जो बात कही गई है वह बिलकुल गलत है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतनी तरक्की को ये ब्रेक लगाना चाहते है और कांग्रेस यह बात हमेशा करती आ रही है।

श्री राजनारायण : मै अपने भाई से यह जानना चाहता हूं कि पंजाब और हरियाणा की बीच में चंडीगढ़ और फाजिल्का के सम्बन्ध में जो माना हुआ, क्या हमारे पंजाबी भाई उससे इन्कार करते हैं ?

श्री उपसभापति : इसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठ जाइये।

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : तो मैं यह कह रहा था कि यह हमारी बदकिस्मती है कि जो पंजाब इतनी तरक्की रह रहा था, उस पंजाब की सरकार को कोई रिएक्शनरी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैं जानता हूं कि जहां इन लोगों की गवर्नमेन्ट हैं, वहां के लोगों का मेआरे जिन्दगी क्या है। मैंने अच्छी तरह से देखा है कि बंगाल की और केरल की क्या हालत है। जो पंजाब की सरकार को रिएक्शनरी कहते हैं वे पंजाब में जा कर देखें कि पंजाब में तरक्की की हालत क्या है। आज पंजाब का खेत मजदूर 6 रु० रोज लेता है, लेकिन बंगाल का खेत मजदूर डेढ़ रुपया रोज नहीं कमाता होगा। मुझे खेद है कि पंजाब की सरकार को तोड़ने के लिये इस केन्द्रीय सरकार ने दो दफा कोशिश की। पहली दफा गिल को खरीदा गया। लक्ष्मण सिंह गिल को खरीद कर के वहां पर अल्प मत सरकार कायम की गई और उस सरकार को सपोर्ट किया कांग्रेस ने। यह सब इसलिये किया गया कि कांग्रेस ने यह देखा कि अगर अकाली सरकार वहां पांच साल चलती रही और वह इसी तरह तरक्की करती रही

[सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा]

तो हमारे पैरों से जमीन निकल जायगी। दूसरी दफा अब फिर वहां अकाली सरकार चल रही थी, तो यहां केन्द्रीय कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड ने यह पास किया कि हमें पंजाब की अकाली सरकार तोड़नी है। कई भाइयों ने कहा कि वहां जनसंघ और अकालियों की फिरकापरस्त सरकार थी, इसलिये उसको तोड़ा गया। लेकिन मैसूर में कौन सी सरकार थी। गुजरात में कौन सी सरकार थी और बिहार में किस पार्टी की सरकार थी। वहां तो कांग्रेस (ओ) की सरकारें थीं और उनको फिरकापरस्त सरकारें नहीं कहा जा सकता। 1967 से लेकर 1971 तक इन का एक ही मंशा रहा है कि डिफेक्शन करा कर दूसरी पार्टियों की गवर्नमेंटों को तोड़ा जाय। सुलतान सिंह जी ने कहा है कि डिफेक्शन चौधरी चरण सिंह जी के समय से हुए। यह गलत बात है। डिफेक्शन का रिवाज शुरू किया कांग्रेस ने। पंजाब में जब प्रताप सिंह कैरो जी की गवर्नमेंट थी तो वहां कांग्रेस के 95 मेम्बर थे और 19 अकाली पार्टी के मेम्बर थे। उन 19 अकाली मेम्बरों में से दो को तोड़ कर सरकार प्रताप सिंह कैरों ने अपनी पार्टी में मिला लिया। तो डिफेक्शन की शुरुआत वहां से हुई। मैं तो कहता हूं कि अगर कांग्रेस डिफेक्शन को बुरा मानती है तो आप उसके लिए कानून क्यों नहीं बनाते हैं। यह कानून इसलिये नहीं बनाते हैं कि इनको पता है कि इनकी ऐसी कार्यवाई रही है कि लोग इनको वोट नहीं देंगे। एक दफा इन्होंने 'गरीबी हटाओ' का नारा लगा कर लोगों को ठग लिया, लेकिन यह ठगी हमेशा नहीं चलेगी। इसलिये यह डिफेक्शन को बरकरार रखना चाहते हैं। यह समाचार-पत्रों में निकला है कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड के फैसले के बाद डा० शंकर दयाल शर्मा एक करोड़ रुपया ले कर पंजाब गये ताकि वहां के मेम्बरों को खरीदा जा सके। उन्होंने खरीदो फरोख्त शुरू भी की थी, लेकिन मैं वहां के गवर्नर डा० पावटे की तारीफ करता हूं कि गवर्नर साहब ने वह जो सौदेबाजी होने वाली थी उसको खत्म कर दिया। कुछ रुपया खर्च भी हुआ, लेकिन मैं इसके लिये मुबारकबाद देता हूं गवर्नर साहब को कि आपका बहुत सा रुपया बच गया जो आप और किसी गैर-कांग्रेसी सरकार को तोड़ने में खर्च कर सकेंगे। इसके लिए आपको भी गवर्नर पंजाब का धन्यवाद करना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे सिर्फ दो बातें और कहनी हैं और वे केवल दो मिनट की बातें हैं। यहां पर करप्शन की बात चली है कि अकाली मंत्रिमंडल भ्रष्टाचारी था। मैं कहता हूं कि मैं इस बात का दावा नहीं करता कि वहां भ्रष्टाचार था ही नहीं। आज युग कौन सा है। इस युग में इन कांग्रेसी भाइयों ने भ्रष्टाचार के सिवाय और सिखाया ही क्या है? मुल्क को इन्होंने 23 साल भ्रष्टाचार ही सिखाया है और यह भ्रष्टाचार कदम-कदम पर होता है। मैं कहता हूं कि बाहर के लोग भारत के लोगों पर हैरान हैं। भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी को लोगों ने खूब वोट डाले और अपने पुत्र के नाम पर छोटी कार के कारखाने का लाइसेंस दे दिया। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं था? इसके सिवाय और भी बहुत सी बातें हैं। जगजीवन राम जी पर आरोप लगे थे और यह सारा भ्रष्टाचार उन्होंने ही सिखाया 25 सालों में इस मुल्क को और इन्होंने सिखाया क्या है। यह समाजवाद की बातें करते हैं। समाजवाद कैसे आ जायगा जब तक आप कुछ पैदा नहीं करते हैं। मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचार इन लोगों की पैदावार है और भ्रष्टाचार मैं मानता हूं कि सब जगह है और हमारे मंत्रिमंडल में भी जरूर भ्रष्टाचार मंत्री रहे होंगे। तो मैं कहता हूं कि यह सुनहरी मौका है, उन लोगों के लिए जो स्टेजों पर और प्रेस में और इस हाउस में बातें करते हैं और उनको यह मौका मिलता है कि वहां गवर्नर का राज है, यानी केन्द्र का राज है, इसलिए इस केन्द्र के राज को चाहिए कि वहां के भ्रष्टाचार के लिए एक कमीशन बिठाये

और शुरू से लेकर आज तक 20 साल की सारी बातों का पता लगाया जाय कि कौन कितना भ्रष्टाचारी है और कौन नहीं है । मैं एक बात और कहना चाहता हूं ''

श्री उपसभापति : नहीं, अब आप बैठें । आप का समय समाप्त हो गया है ।

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : अकाली दल की तरफ से सिर्फ मैं ही हूं ।

श्री उपसभापति : आप अच्छा बोल रहे हैं ।

श्री राजनारायण : इसी लिए मैं सुनना चाहता हूं ।

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : तो आप भ्रष्टाचार के लिए एक कमीशन नियुक्त करें और उस कमीशन के दायरे में तमाम पोलिटिकल आदमी जो आज तक किसी भी पद पर रहे हैं, उनको शामिल किया जाय । मैं उसका स्वागत करूंगा और मैं कहता हूं कि ऐसा एक कमीशन जरूर बनाना चाहिए और आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पंजाब एक सरहदी राज है । उस राज के लोग मेहनती हैं । वे अच्छे किसान और अच्छे सिपाही हैं । वे अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे डाक्टर हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं और हर बात में पंजाब देश को लीड देता रहा है, लेकिन इस राज से हर क्षेत्र में वितकरा किया जा रहा है. मैं कहता हूं, ज्यादा देर तक भेद भाव महंगा पड़ता है । बगला देश में यह सारा खून खराब क्यों हुआ ? वितकरा के खिलाफ हुआ, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हुआ । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप वितकरा को बन्द कर के पंजाब के हितों का खयाल करें और आखिर में मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि जो भूपेश गुप्त जी ने कहा कि वहां भूमि सुधारों में खामियां हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि यह अकेले पंजाब में ही नहीं हैं, यह हर राज्य में हैं । मैं यह चाहता हूं कि ऐसा कोई कानून बने जो हर राज्य के लिए यकसां हो और मैं समझता हूं कि पंजाब में जो भूमि सुधार हुआ है वह काफी अच्छा है, लेकिन उससे आगे और भी अच्छा होना चाहिए । उसमें जो कमियां हैं, खामियां हैं, वह दूर होनी चाहिए । लेकिन बाकी राज्य जो हैं जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, वहां आप भूमि सुधार की बात क्यों नहीं चालू करते । वहां भूमि के कानून बड़े निकम्मे हैं । पंजाब से ज्यादा निकम्मे हैं । इस लिए अंत में मैं फिर आपका धन्यवाद करता हूं और सरकार से यह कहना चाहता हूं कि वह पंजाब के साथ वितकरा बंद करे ।

श्री गुरमुख सिंह मुसाफिर : एक्सप्लेनेशन के लिए मैं कहना चाहता हूं कि डिफेक्शन की बात जो उन्होंने कही है कि प्रताप सिंह के वक्त पिचानवे उनके साथ थे और 19 अपोजीशन में थे और उस समय तीन का डिफेक्शन कराया गया । यह बात कोई मान नहीं सकता कि जिसके पास 95 की फालोइंग हो वह तीन को डिफेक्ट कराये । कांग्रेस के पास शक्ति थी और अकालियों में जो काबिल आदमी होते थे . . .

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : वह डिफेक्टर को क्यों ले आये ?

श्री गुरमुख सिंह मुसाफिर : मेरी बात सुनिये । अकालियों में जो काबिल होते थे और मेम्बर बन जाते थे तो भी मिनिस्ट्री उनको नहीं मिल सकती थी, इसलिए वह चाहते थे कि कांग्रेस में जायें तब कोई मिनिस्ट्री मिलेगी । लेकिन 95 जिसके पास हों वह 3 को डिफेक्ट कराये यह कोई ठीक मानने की बात नहीं है ।

5 P.M.

श्री उपसभापति : अच्छा ठीक है, आप बैठिये ।

श्री गुरमुख सिंह मुसाफिर : एक दूसरी बात बड़ी काबिले-गौर है—कि जिस वक्त मैं चीफ मिनिस्टर था . . .

डा० भाई महावीर (दिल्ली) : आपने डिफेक्शन का जो कहा, उसके लिए जो सबूत दिया वह कुछ समझ में नहीं आया।

श्री गुरुमुख सिंह मुसाफिर : 1967 में जब मैं वहां बतौर चीफ मिनिस्टर था, तो 48 कांग्रेस के कामयाब हुये थे और अगर 53 हो तो कांग्रेस की मिनिस्ट्री बनती थी। यह सत्ताधारी की बात करते हैं। उस वक्त भी हमारी श्रीमती इन्दिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थीं और श्री कामराज हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तो मैं आपको सच कहता हूं कि सात-आठ आदमी अकाली के मेरे घर पर कितनी देर बैठे रहे। मैं तो थोड़ा बहुत चाहता था क्योंकि मुझे वहां से उखाड़ा गया था और मैं चाहता ही था कि मैं अगर नहीं बन सकता तो कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन मेरे चाहने के बावजूद भी कांग्रेस मिनिस्टरी की सेंटर ने इजाजत नहीं दी, न प्राइम मिनिस्टर ने और न कांग्रेस हाई कमांड ने इजाजत दी कि अकालियों में से तोड़ कर अपने 53 पूरे कर लें और मिनिस्टर बना लें, यह इजाजत नहीं दी। तो यह जो कहते हैं कि वहां डिफेक्शन करवाया गया, उसके लिये मैं कहता हूं कि वहां हमने डिफेक्शन को डिसकरेज किया।

श्री राजनारायण : यह किस सन् की बात है।

श्री गुरुमुख सिंह मुसाफिर : यह 1967 की बात है। मैं पहले कह चुका हूं, उस समय 48 आदमी कांग्रेसी चुने गए थे और अगर पांच और होते तो मिनिस्ट्री बन सकती थी, लेकिन हाई कमांड ने इजाजत नहीं दी कि आप दूसरी पार्टी के पांच आदमियों को तोड़ कर मिनिस्ट्री बना लें। फिर बन गई सरदार गुरनाम सिंह की मिनिस्ट्री।

श्री उपसभापति : यह सब बातें बताने की जरूरत नहीं है। इस तरह तो यहां पर सवाल जवाब होते रहेंगे।

श्री गुरुमुख सिंह मुसाफिर : तो कांग्रेस ने डिफेक्शन शुरू नहीं की।

श्री उपसभापति : आप बैठिये, मिनिस्टर को जो जवाब देना है वह कह देंगी।

श्री गुरुमुख सिंह मुसाफिर : अब भ्रष्टाचार की बात आई। गवर्नर सबसे नेक काम यह करे कि एक कमिशन मुकर्रर कर दे और सब की वह जांच-पड़ताल कर ले।

श्री गुरचरण सिंह टोहड़ा : वह डिफेक्शन की बात कह रहे हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं...।

श्री उपसभापति : नहीं, आप बैठिये, अब बताने की जरूरत नहीं है।

श्री राजनारायण : वह जब इतना बोले तो उनको भी जवाब देने का मौका दीजिए।

श्री उपसभापति : इस तरह तो फिर सवाल जवाब होता ही रहेगा।

श्री गुरचरण सिंह टोहड़ा : मैं सिर्फ इतना कह दूं कि उस वक्त जो दो आदमी थे, उनमें से वजीर बनने वाला कोई नहीं था, एक शेड्यूल्ड कास्ट का था और एक लावाना था, उनको डिफेक्ट कराया गया, खरीदा गया, उनमें कोई वजीर बनने वाला नहीं था, उनमे कोई इसके लायक नहीं था। एक का नाम दिलीप सिंह था और एक का नाम चौधरी हरी सिंह था।

श्री उपसभापति : अच्छा बैठिये।

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : Mr. Deputy Chairman, Sir, I s and on my tip-loe because this, is going to be my first participation in this august House which is supposed to crystalise the cool and collective wisdom ot the entire elders here. I have heard with rapt attention the various arguments brought forward by the people oq tjjis side and by the Members on the

opposite side and with your permission, if I mny be permitted to say so, most of the speeches were full of sound and fury, though I cam >t say that they signified no hiig but I :in safely say that they spoke the language of eloquence, they spoke the language of so in J, they sr>oke the language of fury, thoJgh it may or may not be necessarily the language of action, as Mr Gupta pointed out some time back. 1 have heard that the Budget can cover any subject under the sky and I take it it is a very very wide subject too but to-day, for the first time—and I have b^en in the Assembly and in the Parliament for some time—it was a revelation whei I found that people not only covered a I the subjects under the sky but they drilled deep into the underworld. They have imputed motives where none existed. I have found that they said some of the Governors have been used to receiving secret instr icions. I can only say that that shows a very fertile imagination and I would like to congratulate the Members, though I would mt like to name them but I thin* it sho,vs the very very deep fertile imagmathn becmse I do not think we can use our Governors as rubber-stamps. We may or may not agree with the Governors. Tney may or m ty not have acted correctly to our standard but since we have not laid do-vn any guidelines, since we have not olined any ru'es for our Governors so far, I do not thiik it would be in the fitness of things to say that this Governor did right ana this Governor did wrong but at the same lim; to impute motives does not behave us as Members, as representing one million people as we stand to-day. and therefore through you I would like to request all the vlemners here that I think that it is most ui;al!ed for especially to those people vho are not in a position, either the Governor or any ordinary man— I would not say it applies only to the Governor but to any citizen who enjoys the Fundamental Rights in this country, who does n:;t have the power to come and justiiy himself here -I think that does not behove to dignity.

I am afraid that such conduct is not becoming the standard of this House or the other House or of any s andard, if we go on condemning people in puolic life. Here the Governor is a tecongnised institution, Governorship is a recognised institution. I know that many of our Members here believe in Governorship. I think there are many who believe that the red-carpet should 1-e unrolled. 1 think there is fome justi fica'ion in that, till we have that institution. It is an accepted principle and I do not think we can rub it too much. As such I hope hon. Members will agree that we do not want our Governors to be rubber-stamns. We want them to be independent people We want them to be people of good calibre, integriy and character. We know that i.i our own cou try there have been many who have faced many physical disturbances, but they have sPod for their principles. That is one word about Governorship.

The other is about the toppling game. [do not know how far the Congress has been playing the toppling game, but 1 know it very well that theie 1 as been a stir in the country. This has been an ideological battle. Some forts have held long enough, but I do not think there is any fort or fortress in the country which can hold any longer. When we ook aiound us here and in the other House, we find that all the front bench people have gone. All the people who have shone as luminaries have been denuded from those Benches. All the first, top-ranking leaders of the opposition have gone. I do not think that was due to toppling. 1 think it was only due to the ideo ogical battle and the massive mandate that we have received from the public is enough evidence. I do not understand how many of us, who profess by our Constitution here, are prepared to make a mo:keiy of tie Constitution. When we are elected by the people, if we win by one vote, we win and if we lose by one vote we are the losers. We should have the courage to accept it with grace. I am sorry what we here see today is very much an evidence of frustration. We are a great nation. We have had a great past and 1 am sure we shall have a muih greater future before us. It is not only from this side, but Irom that side a.so and as such 1 would appeal to all the hon. Members, let us not fight. Let us not quarrel. Let us not become small people in these matters. Let us rise as ciuzei.s of a big country to face bigger issues. As such I would appeal, let us not be smad-minded in these matters. 1 can say one thing. It may be a toppling game, as you have ascribed it, so far as we are concerned, but I think fiom your side it is a losing game. Today I have enough evidence to show that it is a political game because you

[Shrimati Sushila Rohtagi] are frustrated, and rightly so, that the Maintenance of Internal Security Bill should not come. 1 think >ou played a very successful fame and rry ccnj;raiulations to you, but den.ccrE.cy has its own processes. You can delay it for some time. You can filibuster for some time, but you cannot puil it out. You cannot carry on the game of toppling. So, I do not agree altogether with the charge that we have indulged in the toppling game.

Then, there is the other charge about defections. I agree with all the hon. Members here that defection is a wrong thing. It is a stigma in the political life of the twentieth century. I think all of us, irrespective of party affiliations, must contribute our mite and see that the stigma is removed from our national life. Whatever be the reason, the Government has not brought forward this Bill. There may be poliiical reasons. I am sure there must be political reasons, but that does not mean that the stigma does not exiit. We must try and endeavour in that direction till this is rooted out. Personally I am of the view that the moment a person decides to change his ideology, he must quit the party, go straight to the public, seek re-election and get re-elected on the basis of the ideology in which he believes. I think this is the only correct way and for that it may be necessary vo bring forward an amendment in the Representation of the People Act. That may take some time, but 1 think public opinion must be mobilised instead of hurling abuses at each other. I am sorry that for the last few hours the entire atmosphere has been surcharged with corruption, nepotism and there seems to be a crisis of faith. I am afraid this does not reflect the will or the spirit or the soul of our great country. This is oniy reflecting the diseased mind of seme people who prefer to say things which do not exist, who decide to put things in a manner that will not only recoil on us bui also on our great nation, which will have a very bad effect so far as our country in the int'.rnational comity of nations is concerned.

1 am asking Mr. Rajnarain, if v e and all of us go *on* criticising ourselves and calling ourselves corrupt people, what right have we to ask the other nations to say that we are not corrupt ? I hope you and jour party will realise the irreparable damage that you are doing. . .*(Interruption)* That was long overdue. I am sorry it has happened now.

There is one point. It has been a blessing in disguise, this little contioversy about my being in possession of the floor and my being dispossessed of the f oor of the House. There was a little wrangle, I did not object to that, but that has been a blessing in disguise because indirectly I have gained two very esteemed friends today, Mr. Rajnarain and Mr. Bhupesh Gupta. These are two big names and they have extended to me iheir hand of friendship, and 1 also reciprocate and 1 consider it to be an honour. But a doubt arises in my mind and I feel you will share that view also. When Mr. Rajnarain who extends his friendship to me with one hand and at the same time says "Sushilaji is standing like stfTfi^r BTTV$_I$ I do not understand.

srrq^ w&, <Pifcrtr ^\ ^ | Now *l* am quoting your words which you have forgotten long ago, but I have got that in my mind.

श्री राजनारायण : यह मैंने सुशीला जी के लिए नही कहा । सुशीला जी डेमोक्रेटिक संत को समझें । बल्कि जिस सरकार को वे रिप्रेजेन्ट कर रही हैं, उस सुशीला की सरकार को कहा ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं आपकी आभारी हूं ।

श्री राजनारायण : सुशीला जी और सरकार में बहुत फर्क है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : बहुत फर्क है ।

श्री उपसभापति : राजनारायण जी, आप बैठ जाइये ।

(Interruptions)

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : 1 have heard you for ho'irs and I could go on hearing for hours. *(Interruption)* Mr. L cputy Chairman, today incidentally when J sland here or when I sit here it was as a n tmber of the Council of Ministers. If he can extend his hand of friendship and call that friendship l|4T ^ifa^T I wonder how he is going to treat his enemies. That is something which is beyond my comprehen-

sion and I think it will fake years for me to uuderstaud. 1 pity his adversaries and enen.ies, that is all I can say.

There is another anomaly, incompatibility. Sir He said : Sf 3|cT *QTft ^m^* I am very grateful for that. But *'ka'tT* need not necessarily be STT5T ^STT?. He mav have committed a coolly calculated and pre-meditated act of murder. How can a *'katiV* and flT<T J'S'TTT? go together ? That also shows a little lack of understanding.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मुझे कहने का मौका दीजिए ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : नहीं, मौका आपको बहुत दे दिया गया है ।

श्री उपसभापति : अब कोई आवश्यकता नहीं है ।

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : I will not provoke him any further No more provocation, I seek your indulgence.

श्री राजनारायण : तुम्हारे बगल में कोई चश्मदीद बोल रहा है ।

THE MINISTER OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND MINISTER-IN-CHARGE OF DEPARTMENT OF CULTURES(शिक्षा और समाज कल्याण तथा ?f^f=T f?*TPT inffr (SHRI SIDDHARATHA SHANKAR RAY) : Why try to kill a man who is already dead ?

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : There is another point. I find thit n-osf of Members here were preoccupied, all of them were obsessed with two ideas : t e first one was the Proclamvnn, an issue which has been long deba'ed, discussed and disposed of in this House. I think 80 per cent of the time has already gone on that. I do not see why they should reduce the time allotted to the B idaet. The other point is about internal security. I can quite understand the misgivings, I can quite understand the fears, I can quite understand the things with which their minds are obsessed. But most of the time that was allotted for these two subjects have been aken away by subjects which are beyond their purvtew. To comc to some of the allegations, my friend Mt. Rajnarain has said it was a ^ ms budget ** budget, and above all he used the expression which I feel rather shy of repeating : irp.fr <r ^r | , i am sorry Je may have different interpretations in our reading of the budget, whether it has been constructive or whether it has been good We can always differ. But I thought that we were dealing with a budget of a State which has a place of prided fa the

Punjab is a State of which every Indian has a right of feeling proud. It is a philosophy of the life of the Puojibi, his is a dynamic and scintillating life. He not only works hard but he contributes his might also. And I thought that in a subject like this there would be no two views and that this would be receiving the unanimous approval of this House. But here we find that even a Budget for a Slate like Punjab has received an adjective which I would not like to pronounce, and I can only say that I and 1 am sure the members of my party—would not like to compete with Shri Rajnarain so far as his dictionary and his vocabulary are concerned. That is all that I would like to say. *(Interruptions)* Tyagiji is very much more understanding, I know,

AN HON. MEMBER : He is always on the wrong side.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : The side may be wrong, but he is basically a good man. I never deny it. He is basically a good man. We have all respect for him, whatever his views.

Sir. there are some specific points that I would like to take up. A*"d first of all, it is Mr. Bhupesh Gupta's point that there should be some amendment in the Tenancy Ac and he wanted exemptions on ceilings to be withdrawn. I wish I had more time to dwell on those pcin's. I am quite well aware that many of the suggestions that he his given are really worth serious consideration. And 1 would certainly like to convey them to the proper leencies concerned and sei that pr >per a'teition is oaid to them. il think Government is already acting on

[Shrima'i Sushila Rohtagi] thit line, and land reform? are receiving our active consideration. But it will take a little more time, but we are miking efforts But when he called the politicians as political mannequins. I think that eloquence was uncalled for. We are moving in the direction of land reforms. I would like to tell about the intensive agricultural district programme that about Rs. 21 lakhs have been given to maximise the production of cotton and for the spraying of cotton, about Rs. 65 lakhs. I would like to tell the hon. Menbers who sail thit Fazilka and Abohar have received a step-motherly treatment, that a fpart of that is used for the deve op-ment o triise ve is a'so ani as such, they need not feel that 10 developmental scheme; have bee.i taken up in those areas a'so.

Now, the main oo'nt is about the *mandi** and this was brought out by Mr Man Singh Varma. I am grateful to him for having pointed out this matter But 1 can only te'.l him that it is not the Goven-nrvit which is to blame for this so much Punjab has done very well, it is the granary of the coun ry. And, Sir, it has already exceeded the target, and the time has wme when there is no place to keep it. The stage has come when we cannot provide enough railway wagons, and it should be viewed in the light of a national question, not only a question which should be con-fined only to Punjib. So, I would like to tell Mr Min Singh Varma that even in this direction the Government has taken steps Punjab has alreajy procured about 24 lakh tonnes of wheat as against the original target of 26 lakhs and an all India target of 3.7 m'llion tonnes. The revised target of Punjab is 27 5 lakh tonnes and this will be achieved So he need not have any fear on that side also because Government is already looking at it from that angle.

About power shortage, I do realise that there is a great power shortage in the country, in almost all the States. Coming from UP, I know what it is, and I know that if Punjab did not have a shortage of power, probably it might have done even better. It has done exceedingly well in spite of the power shortage. And in this direction certain special efforts have been made which I 'hink hon. Members would like to know Rs. 15.90 crores have been given lor the power projects in this Budget and Rs. 14.25 multi-purpose projects. An additional capacity of 3500 megawatts is proposed to be installed for which a number of generation of projects would be undertaken. And top prio'ity is also given 'o the execution of the Guru Nanak Thermal Plant in the Brat stage. In the Pumab Eleetricity Bwd they require 54 diesel generating stations of the capacity of 63.24 megawatts And about the Ravi Waters about which we had some controversy with Pakis-an, I would like to tell the House that we are als-goina ahead with the execution of the Thien Dam Project, and the exploration and survey work in this is a'ready going ahead. So. hon. Members need not have any fear on that.

Sir, there was some very strong criticism (rom one of our friends-you can underhand who it can be-there is nc effort in this Budget to "Garibi Hatao". Sir, 1 can only give three or four active steps which have been undertaken by the Government in this direction The first is regarding the State Government employees. A sum of Rs. one cro'e has been given provisionally tor the State Government employees. We know that the Government employees do not belong to a very rich class. So this money is going for their amelioration, certainly to improve their lot. In such a situation we cannot be accused that we are not taking any steps in the direction of "Garibi Hatao".

Secondly, about Rs. 3 crores have been provided for the implementation of the Kothari Commission recommenda'ion. This sum will go towards the revision of the pay-scales of the teichers. We all know that the teachers class is a low-paid class and I do not ihink this amount is sufficient. However, this is a correct step in the right direction and I think it is cenainly in the direciton of "Garibi Hatao" with which the hon'ble Miember may or may not agree.

Thirdly, Sir, we find that about 26 per cent of the State Plan outlay has been earmarked for roads and social services. And roads and social services are not meant for the upper strata of the society. They are meant for the poor classes who can only dream of travelling by road. As such is also a step to ameliorate the lot of the poor people and is a part of the Garibi Hatao campaign.

Irrigation is a'si taking a big share in the Bucket. About 50 per cent of the Budget is going to the Iniga'ion and Power. Inigation -ill c r t t i n l y go to benefit the lower sectioi ef the people and, as such, I think this 50 per cent is going dir^c'ly to ameliorate the condition of the poorer sections As such this Budget is a budget dedicated, if at all, to ameliorate the lot of Ihe Gari'o people Therefore, I ceruinly refute the charge which has been brought forward in this direction.

Let us then ook at the pace of expenditure in Punjab s Fourth Plan. We find that in 1969-78 it was about Rs. 60.04 crores. In 19/0-71 it was increased tj Rs. 65.0ɹ crores, and this year it has gone up;o Rs. 68.23 crores. Let us remember that the utilisation of finance conti ues to be the highest in the country in Punjab and. as such, I would only like to say that ihe growth rale of—May 1 seek your undiluted attention, Mr. R ajnarain ?

श्री राजनारायण : मैं सुन रहा हूं और देख भी रहा हूं ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : कृपा करें केवल 5 मिनट और, ज्यादा समय नहीं लूंगी ।

I was saying that the growth rate of economy has been going at the rate oi 6.9 per cent in 1^70-71. I thing Punjab has done extremely well. In the matter ot foodgrains a so Punjab has been seriously following the Fourth Plan target of 6.7 per cent growth per annum.

Sir, one point remains about education. I t h i n k 1 have also some affinity with education having ome from that line. 1 share the co icern shown by my hon'b e friends. According 'o the Acharya Naren-dra Dev Comm ttee 20 per cent of the total funds should have gone to education. I am extremely happy to tell Mr. Rajnarain as well as this side of the House that the exp.ndi ure on education is about 2'J per cent of the total revenue ; Rs. 32 crores out of Rs. 160 crores works out to 20 per cent on education. 1 am very happy that there is a smiie on the hun'ble Member's face. Therefore, education is receiving our full attention.

Atout Harijan scholars I was rather disturbed when I heard one of our Members challenging and say that nothing has been done to the poor children of the Hanjans. I am g iJ to announce that the sons and daughteis of pirents having an Income up to Rs. 3,600 are now eligible for scholarships instead of an income of Rs. 1. 00. That is to say, a large number of students will now receive concessional scholarships ana exemption from fee.

The rate of scholarship? in the case of the firs and the second division students has also been rais-d from Rs. 6 to Rs. 10 per month. So, I say that his Government which is accused of not being a socialist Government is working in that direction whether our accusers like it or not. This is a blunt fact. With these words I would only repeat one line about the actual p iysical position, that is, about the b »ck-ward c.a»ses and the Scheduled Cases and the Sc ledu'ed Tribes. It was a charge that we are doing nothing for the welfare of the Scheduled Castes and the backward c asses. A programme for the contsruction of *dharamshalas* and *chaupuls* has been laun-ched. As many as 1600 villages are expected to be covered by the end of U71-72. A sum of Rs. 50 lakhs has beed allocated for this year.

In the Budget we find that revenue receipts ate placed at Rs. 161.37 crores.

The expenditure on revenue account is Rs. 149.36 crores. So, the surplus on revenue account is Rs. i2 Oi crores. However, there is an overall deficit of Rs 4.29 crores. This will be met by larger collections of taxes and the devolution from the Centre. With these. Sir, I think the major criticisms which have been hurled at us will be met. All I would like to say 's that it would have been better if this Budget had been debated in the Punjab Assembly itself. And the only reason why it has not been done is—let me be frank ; let me confess—that we sometimes fail to rise as a nation: We lack certain things. And let us not forget that this game of horse-trading or defection or toppling or opportunism of whatever it may be known as, is not because something is offered, but it is because we accept it. It involves our own moral fibre ; it is our own weakness. If we are I not prepared 10 accept, no one can force us to accept. 1 think that every action **I that we take on the floor of the House,**

[Shrimati Sushila Rohtagi]

every word that we utter here, should be taken in a manner that it goes round the country, it reverberates, and the people will judge us by what we do. With these words, I would only request hon. Members to wipe away the tears from their eyes. Let them forget that their parties have lost. Let them forget that they have not come back with a massive mandate which they expected to get. Let us remember that we are a great country and work in a united way. With these words. Sir, I commend the Budget for the acceptance of , the House.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The discussion on the Budget is over. Now we 1 shall take up the Appropriation Bill, j Shrimati Rohatgi may move the Bill for | consideration.

THE PUNJAB APPROPRIATION BILL, 1971

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE/faccT IT-^IWI ^ 3<m:3tr (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI) : Sir, I beg to move :

"That the Bill to authorise payment and appropriation of cer'ain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Punjab for the services *o(* the financial year 1971-72, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

'J he question was proposed.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) : Sir, . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You have said enough in your speech on the Budget.

SHRI BHUPESH GUPTA : A few words, Sir, We have been treated to a very excellent speech. But as 1 was Listening to her, I felt I was not so much hearing the Minister piloting a Finance Bill, rather 1 was bearing a budding Home Minister or, shall I say, blossoming Home Minister. I think "blossoming" would be more appropriate when I address this *woi'd* to the hon, Minister. Well she has spoken with gusto, with eloquence, with passion without being passionate, and she has made certainly some little impression on some of us . . .

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING/ निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (SHRI I. K. GUJRAL) : Also on Mr. Rajnarain.

SHRI BHUPESH GUPTA : ... although she is as ignorant about the Budget she was talking about as I am ignorant about it. After all, she has to speak on the Budget, having got the brief from the officials. So, I have to speik here from the Opposition when we are confronted with a proposition of this kind and that, too, by a lady.

Now, Sir, I do not know why she brought in Punjab heroism. Is it in doubt ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND MINIS-TER-IN-CHARGE OF DEPARTMENT OF CULTURE/शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री, संस्कृति विभाग मन्त्री (SHRI SIDDHARTHA SHANKAR RAY) : Why did you bring in bank nationalisation ? It is as irrelevant as anyt ling else.

SHRI BHUPESH GUPTA : Punjab heroism has never been in question. None of us questioned the heroism, sacrifice, courage and the suffering of the people of Punjab. What we were questioning was the leadership that has crime to rule Punjab for some time alternating between Congress leaders and Akali leaders. Even now, I read in the paper that one Mr. Prabodh Chandra, supposed to be a leader of the Congress Party in Punjab, committed to everything revolutionary on earth, does not know the difference between left and the right. He asked, what is this talk about the left and the right ? I do not know. But such leaders we have got. It is they who have made a mess along with our Akali friends. My Akali friend spoken in heroic terms, I must say. But it is very difficult to win the heart of a lady, as you *know.*